राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 21 जनवरी 2026 वर्ष-8,अंक-325 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

नए सेनापति ने संभाली भाजपा की कमान

पीएम मोदी बोले : मैं कार्यकर्ता, वे मेरे बॉस, अब मेरे काम का आकलन करेंगे

'पीएम मोदी से सीखा जनभावना से जुड़ने का पाठ', बोले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन

एजेंसी

नई दिल्ली। नितिन नबीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मोदी ने कहा ह्यभाजपा ऐसी पार्टी है, जहां लोगों को लगता होगा कि मोदीजी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए हैं। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं BJP का कार्यकर्ता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि नितिनजी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं। अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। इससे पहले नबीन

दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब और झंडेवाला मंदिर गए और माथा टेका। भाजपा मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे। किसी और उम्मीदवार का नामांकन न आने से नबीन निर्विरोध चुने गए। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि

हमने कार्यकर्ता के तौर पर पीएम मोदी के देशसेवा के काम करते हुए देखा। आपको देख कर ही सीखा है कि जो व्यक्ति खुद को लोगों की भावनाओं से जुड़ने वाला बना सकता है, वही बड़ा शख्स बनता है। पीएम ने कहा, आज का पल हम सबके लिए बहुत विशेष पल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनका एक एक शब्द हमारी आगे की दिशा होगी। उनका मार्गदर्शन हमारी पूंजी होगी। मैं भी कार्यकर्ता के तौर पर अपने काम का हिसाब दे रहा था और अब वो मेरी सीआर लिखेंगे। पीएम मोदी ने कहा, ह्यसाथियों देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। जब मैं यह कहता हूं तो अर्बन नक्सल मैदान में आ जाते हैं। वे कहते हैं फलाने का बेटा बेटी, हम किसी की प्रतिभा के विरोधी नहीं है। दुर्भाग्य से कांग्रेस में एक के बाद एक उनके परिवार के अध्यक्ष ही बनते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता को उनके विचार से कोई लेना देना नहीं। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। परिवारवाद की राजनीति ने देश के युवाओं के लिए राजनीति में आने के रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए मैं एक लाख ऐसे युवाओं को राजीनिति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार से वे पहली बार राजनीति में आएंगे। पीएम ने कहा, ह्यदुनिया के बड़े देश भी अपने यहां घुसपैठियों की जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको नहीं पूछ रहा है।

स्कूल फीस वाले कानून पर 'सुप्रीम' सख्ती

■ पूछा: सत्र के बीच क्यों लागू किया नियम

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल फीस को नियंत्रित करने वाले नए कानून को लागू करने के समय को लेकर दिल्ली सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। अदालत ने कहा कि जब शैक्षणिक सत्र पहले से चल रहा है, ऐसे समय में कानून लागू करना भ्रम की स्थिति पैदा करता है और इसे जमीनी स्तर पर लागू करना मुश्किल हो सकता है। यह टिप्पणी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई।सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को जिस समय लागू किया गया है, वह व्यावहारिक नहीं दिखता। अदालत ने संकेत दिए कि कानून अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसका क्रियान्वयन तय समय-सीमा के अनुसार होना चाहिए। पीठ ने कहा कि नियम लागू करने में जल्दबाजी से स्कूलों, अभिभावकों और छात्रों तीनों को परेशानी हो सकती है।दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित इस कानून में स्कूल फीस से जुड़े सभी मदों को स्पष्ट करने, खातों में पारदर्शिता लाने और अतिरिक्त शुल्क लगाने पर रोक लगाने का प्रावधान है। कानून के तहत कैपिटेशन फीस पूरी तरह प्रतिबंधित है और बिना मंजूरी के किसी भी तरह की अतिरिक्त वसूली को अवैध माना गया है।

हल्के सुधार के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची फिजा

■ सांसों पर संकट बरकरार

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 397 दर्ज किया गया, जिससे हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि, सोमवार की तुलना में इसमें मामूली सुधार देखा गया, जब एक्यूआईज 418 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में था।सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ा रहा। आनंद विहार और अशोक विहार जैसे इलाकों में एक्यूआई 444 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर में यह 446 तक पहुंच गया। अन्य प्रमुख प्रदूषित क्षेत्रों में पंजाबी बाग (437), आरके पुरम (421), बवाना (418), आईटीओ (414), चांदनी चौक (412) और द्वारका सेक्टर 8 (412) शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है।

यूपी में परिवार के 4 लोगों की हत्याकर जान दी

पत्नी, दो बेटे और मां के माथे पर गोली मारी, अमीन ने खुद पर 2 फायर किए

सहारनपुर। सरकारी अमीन ने पत्नी, दो बेटों और मां के माथे में गोली मारकर हत्या कर दी। फिर खुद के सीने और माथे पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पति और पत्नी का शव फर्श पर, जबकि मां और दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। अमीन के पास तीन तमंचे पड़े मिले। वारदात का पता उस वक्त चला, जब बहनोई ने कई बार कॉल किया। फोन नहीं उठा तो उसने बेटे को घर भेजा। बेटे ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद खिड़की तोड़कर अंदर गया, जहां सभी के शव पड़े मिले। सूचना पर डीएम मनीष बंसल और रस्ढ आशीष तिवारी मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि सिंचाई विभाग में तैनात अमीन

अशोक

अशोक डिप्रेशन में था। चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा था। रस्ढ का कहना है कि शुरूआती जांच में सामने आया है कि अमीन ने पहले परिवार के लोगों को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। मृतकों में अमीन अशोक राठौर (40), पत्नी अंजिता (37), मां विद्यावती (70) और दो बेटे कार्तिक (16) और देव (13) शामिल हैं। वारदात का पता चलते ही अमीन की पत्नी की बहन पहुंची और रो-रोकर बेसुध हो गई। पूरा मामला सरसावा थाना क्षेत्र की शाश्वत बिहार कॉलोनी का है। अशोक अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह मृतक आश्रित में नौकरी पाए थे। वह नकुड़ तहसील में अमीन थे। शाश्वत बिहार कॉलोनी में 5 महीने पहले अमीन ने दो मंजिला मकान किराए पर लिया था। मकान मालिक देहरादून में रहते हैं। वह CRPF में सब-इंस्पेक्टर हैं। दूसरी मंजिल पर अमीन का परिवार रहता था। बेटा देव कस्बे के MTS पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था।

तमिलनाडु गवर्नर का बिना स्पीच दिए विधानसभा से वॉकआउट

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में फिर हाईलेवल ड्रामा हुआ। राज्यपाल आरएन रवि एक बार फिर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए स्पीच दिए बिना ही असेंबली से बाहर चले गए। पिछले सालों की तरह गवर्नर ने कहा कि तमिल गान के बाद राष्ट्रगान बजाया जाए। लेकिन स्पीकर अप्पावु ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गवर्नर रवि शुरूआती भाषण पढ़े बिना ही विधानसभा से बाहर चले गए। इससे पहले 2024-25 में भी वे

ऐसा कर चुके हैं। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उनके भाषण में रुकावट डाली गई। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं। राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। गवर्नर के वॉकआउट के बाद विपक्षी AIADMK के नेता भी असेंबली से बाहर चले गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

खरगे एवं राहुल बोले: मनरेगा की जगह नई व्यवस्था रेवड़ी

एजेंसी

, वीबी-जी राम जी से छिना ग्रामीणों का काम का अधिकार

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लागू किए गए नए वीबी-जी राम जी अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण भारत का काम का अधिकार खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आरोप लगाया कि अब ग्रामीणों को काम अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि सरकार की मर्जी से रेवड़ी की तरह दिया जाएगा।गांव के लोगों

को लिखे पत्र में खरगे और राहुल ने कहा, यह नया कानून राज्यों पर आर्थिक बोझ भी डालता है और गरीबों के हक को कमजोर करता है। 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून बनाकर ग्रामीणों को कानूनी रूप से काम का अधिकार दिया था। इससे अब तक 180 करोड़ से ज्यादा मानव-दिवस का रोजगार पैदा हुआ, करीब 10 करोड़ परिसंपत्तियां बनीं और पंचायतों को मजबूत किया गया। लेकिन, नई योजना में न तो 15 दिन में काम देने की गारंटी रहेगी, न न्यूनतम मजदूरी की। मजदूरी तय करने और काम देने का फैसला केंद्र सरकार करेगी। साथ ही पंचायतों की ताकत खत्म कर ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जाएगा।पत्र में कहा गया कि अब मजदूरी का 40 प्रतिशत बोझ राज्यों पर डाला जाएगा, जिससे काम के दिन कम हो सकते हैं।

किश्तवाड़ में आतंकवादियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी

एजेंसी

किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। इसी बीच जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने को खोज निकाला। इसमें भारी मात्रा में राशन और सामान जमा था। पत्थरों से बनाए गए इस हाइड आउट को तिरपाल से छिपाया गया था। इसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, गेहूं का आटा, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स, अधपके अंडे और ताजी सब्जियां मौजूद थीं। फर्श पर मिले कंबल बताते हैं कि ठिकाने का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा था। वहीं राशन की मात्रा से अंदाजा लगाया

जा रहा है कि आतंकी यहां लंबे समय तक रुकने वाले थे। सुरक्षाबलों का दावा है कि आतंकियों तक यह पूरा राशन और सामान बिना लोकल सपोर्ट के पहुंच पाना संभव नहीं था। क्योंकि इतनी मात्रा में सप्लाई सिर्फ सीमा पार से नहीं आ सकती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घने जंगल के बीच ढलान पर बना ठिकाना दूर से दिखाई नहीं देता था।

नौसेना प्रमुख बोले: आत्म अनुशासन बहुत जरूरी

युवा होंगे विकसित भारत के एक्टर-डायरेक्टर व दर्शक

एजेंसी

नई दिल्ली। विकसित भारत बनाने में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि युवा ही इसके एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होंगे और कई बार वे ही दर्शक भी होंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कड़ी मेहनत और लगन पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर का उदाहरण दिया। साथ ही नैतिक साहस के मूल्य को समझाने के लिए 1971 के युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी और बलिदान को याद किया। उन्होंने युवाओं से आत्म अनुशासन और टीमवर्क को अपनाने की अपील की तथा जोर देकर कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत काबिलियत से कोई संगठन या देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप इस टीम भावना और युवा ऊर्जा को एकता तथा मकसद के साथ इस्तेमाल कर पाते हैं तो यह 2047 तक विकसित भारत बनने की कोशिश में एक प्रेरक शक्ति बन जाएगी।उन्होंने कहा कि देश की आबादी में करीब 65 फीसदी युवा हैं और इसलिए उन्हें 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस

समय तक उनमें से ज्यादातर लोग 30 के दशक के आखिर या 40 की शुरूआत में होंगे। तो अगर मैं विकसित भारत बनने की इस प्रक्रिया को किसी फिल्म बनने जैसा देखूं तो इस सफर में आप इसके एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होंगे और कई बार इसके दर्शक भी होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय आबादी में 65 प्रतिशत युवा हैं। मैं आप पर नतीजे देने का दबाव नहीं डाल रहा हूं लेकिन आपको काम करना होगा क्योंकि आप आबादी का ज्यादातर हिस्सा हैं। आपको निजी फायदों से ऊपर उठना होगा और यह सोच कि इसमें मेरा क्या फायदा है? इसे अपनी सोच से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं या देश आगे बढ़ता है तो इससे आपको भी नाम मिलेगा। एडमिरल त्रिपाठी ने युवाओं को सोशल मीडिया के प्रलोभन से बचने की हिदायत दी। आत्म-अनुशासन का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया सबसे बड़ा भटकाव है। मोबाइल फोन पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशन अंतहीन ढंग से आपका ध्यान खींचते हैं। यहीं आपके चरित्र की परीक्षा होती है। एडमिरल त्रिपाठी ने जीवन में आत्म-अनुशासन का महत्व बताते हुए कैडेट्स से कहा कि ऐसे में प्रलोभनों को ना कहने का साहस रखें। ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। एक बार संकल्प कर लें तो खुद की भी न सुनें। नौसेना प्रमुख ने युवाओं को सचेत किया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग जीवन में उनके लक्ष्यों के बीच एक दीवार बन सकता है। किसी निगरानी या नियंत्रण में अनुशासित रहा जा सकता है, लेकिन अनुशासन बनाए रखने की असल परीक्षा तब होती है जब कोई

बीएमसी मेयर पद पर सियासी घमासान जारी

अब एकनाथ शिंदे ने ठोका दावा, बोले- शिवसैनिकों की यही भावना

एजेंसी

मुम्बई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को संकेत दिया कि शिवसेना मुंबई के मेयर पद का दावा कर सकती है। उन्होंने इसे पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे के जयंती वर्ष में सम्मान का प्रतीक बताया। शिंदे ने कहा कि यह मांग कुछ शिवसैनिकों की भावनाओं को दशार्ती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई में महायुति गठबंधन का मेयर होगा। शिंदे ने बताया कि महायुति गठबंधन के मेयर उन नगर निगमों में होंगे, जहां शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, बालासाहेब ठाकरे का

जन्मशती वर्ष 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। कुछ शिवसैनिकों की भावना है कि बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। शिंदे ने यह भी जोर दिया कि शिवसेना ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी, जो जनता के जनादेश के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनावों में शिवसेना और भाजपा ने गठबंधन के रूप में हिस्सा लिया था। इस सवाल पर कि शिवसेना ने अपने नए चुने हुए सदस्यों को मुंबई के एक महंगे होटल में क्यों रखा, शिंदे ने कहा कि यह किसी नए राजनीतिक समीकरण के लिए नहीं है।

बताया जा रहा है कि शिंदे चाहते हैं कि कम से कम पहले ढाई साल के लिए बीएमसी मेयर का पद शिवसेना को मिले, क्योंकि यह बाल ठाकरे का जन्मशती वर्ष है। शिवसेना का कहना है कि नव निर्वाचित सदस्यों को होटल में बीएमसी की कार्यप्रणाली के बारे में कार्यशाला के लिए स्थानांतरित किया गया। यह कदम बीएमसी चुनाव परिणामों के बाद उठाया गया। इन चुनावों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 65 सीटों के साथ भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें जीतकर महायुति गठबंधन को 227 सदस्यीय बीएमसी में बहुमत दिलाया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और 28 अन्य नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी 22 जनवरी को आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है। इस लॉटरी से यह पता चलेगा कि मेयर पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा, जैसे सामान्य, महिला, एससी, एसटी या ओबीसी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टैरिफ के बावजूद वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर छू सकती है नई ऊचाईयां

किसी भी देश के नागरिक यदि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना प्रारम्भ करते हैं तो इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कम होता है और देश में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि आज विश्व के समस्त देश एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके चलते उत्पादों का एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात बहुत आसान बन पड़ा है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी कहते हैं स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा।

(लेखक- प्रहलाद सबनानी)

दिनांक 1 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के आर्थिक विकास से सबंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़े 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए है। इस अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। सकल घरेलू उत्पाद से सम्बंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के आधार पर ही वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक विकास से सम्बंधित द्वितीय अग्रिम अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का ही है परंतु भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग का अनुमान 7.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का है। भारत की आर्थिक विकास दर विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक रहने की सम्भावना विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक (7.2 प्रतिशत), फिच नामक रेटिंग संस्थान (7.4 प्रतिशत) आदि संस्थानों ने भी व्यक्त की है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हासिल की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के कुछ मुख्य कारणों में शामिल हैं - (1) केंद्र सरकार के स्थिर उपभोग खर्च में वृद्धि दर जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.3 प्रतिशत की रही थी, वह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (2) विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत की रही थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (3) सकल मान योग में वृद्धि दर का 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है; (4) सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है; (5) सेवा एवं कृषि क्षेत्र में क्रमशः 9.1 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की सम्भावना व्यक्त की गई है; (6) भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर का 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना होना भी शामिल है। अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के खंडकाल में राजकोषीय घाटा 9.8 लाख करोड़ का रहा है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल अनुमान का 62.3 प्रतिशत है, अतः बजटीय घाटा भी अभी तक नियंत्रण में ही रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत होगा। इस प्रकार केंद्र सरकार की आय एवं व्यय से सबंधित स्थिति भी पूर्णतः नियंत्रण में है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को उत्साहवर्धक माना जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि दर ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद रहने वाली है। दरअसल ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ को वित्तीय बाजार में बहुत गम्भीरता से लिया जाकर इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। परंतु, वास्तव में भारत के आर्थिक विकास दर पर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात की कम मात्रा भी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हुए थे, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा था। अतः भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.85 प्रतिशत ही रहे हैं। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है ही नहीं (चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, इसीलिए चीन पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अधिक हो सकता है), भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है। यदि भारत के नागरिक स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं तो ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को शून्य भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भी भारतीय समाज को लगातार प्रेरणा दी जा रही है कि वे भारत में निर्मित उत्पादों का ही उपयोग करें ताकि भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संघ ने पंच परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है, जिसमें पांच बिंदु शामिल किए गए हैं - स्वदेशी का उपयोग, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन। भारत में समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इन संस्कारों में भारत के नागरिकों में 'देश प्रथम' के भाव का जागरण भी शामिल है। लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता नागरिकों की भागीदारी और कर्तव्यों के प्रति सजगता पर निर्भर करती हैं। जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनका ईमानदारी से पालन करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और देश की प्रगति होती हैं। समाज की प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता तथा कटिबद्धता आवश्यक है। करों का समय पर और सही राशि का भुगतान करना नागरिकों का कर्तव्य है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए करों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज की भलाई के लिए स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसी सामाजिक सेवाओं में भाग लें।

किसी भी देश के नागरिक यदि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना प्रारम्भ करते हैं तो इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कम होता है और देश में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि आज विश्व के समस्त देश एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके चलते उत्पादों का एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात बहुत आसान बन पड़ा है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी कहते हैं स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा। संघ ने इसमें एक बिंदु जोड़ दिया- आत्मनिर्भरता, अहिंसा और सादगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह मितव्ययिता से जिए ताकि संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके। परंतु, इसका आशय कंजूसी करना

कदापि नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों के साथ ही केंद्र सरकार ने भी आर्थिक क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं जिसके चलते हाल ही के समय में भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि दर में लगातार सुधार दिखाई दिया है। विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ के प्रभाव को लगभग शून्य करने के उद्देश्य से भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इनमे विशेष रूप से शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम, ओमान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि। यूरोपीयन देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता शीघ्र ही सम्पन्न होने जा रहा है। सम्भवत 27 जनवरी 2026 को इस मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीयन यूनियन एवं भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ से प्रभावित होने वाले उत्पादों के लिए भारत ने अन्य देशों के रूप में बाजार तलाश लिए हैं एवं इन देशों को विभिन्न उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ हो चुका है जिससे नवम्बर 2025 एवं दिसम्बर 2025 माह में भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर हासिल की जा सकी है। वैसे, भारत और अमेरिका के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं शीघ्र ही इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद तो भारतीय उत्पादों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत को भी कम अथवा समाप्त किया जा सकता है, इससे अन्य देशों के साथ साथ अमेरिका को भी भारत से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में और अधिक वृद्धि हासिल की जा सकेगी।

संपादकीय

शांति थोपने की कोशिश

नोबेल शांति पुरस्कार की उत्कट अभिलाषा के मोह में अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के तमाम हिस्सों में जारी अशांति पर शांति थोपने की असफल कोशिश करते रहे हैं। कई देशों में टकराव के बाद शांति की स्थापना की असफल कोशिशों के पश्चात अब ट्रंप गाजा में शांति थोपने का उपक्रम कर रहे हैं। गाजा में शांति स्थापना के लिये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित योजना विश्व की नियामक संस्थाओं के ढांचे से बाहर उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप एक महत्वाकांक्षी कदम है। गाजा में शांति बनाये रखने के लिये मुनाफे व व्यापार जैसी प्रक्रिया के रूप में यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को एक प्रत्यक्ष चुनौती है। जो लंबे समय से दुनिया के सबसे जटिल संघर्षों में से एक गाजा संकट को दूर करने के प्रयासों में लगी हुई हैं। सही मायनों में ट्रंप का यह शांति प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ को दरकिनार करने जैसा है, जिसको लेकर उन्होंने बार-बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दी हैं। उनकी दलील है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अक्षम और पक्षपाती है। वह इसमें अत्यधिक नौकरशाही हावी होने के भी आरोप लगाते रहे हैं। निश्चित तौर पर दुनिया की महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र को हांकने का प्रयास करती रही हैं। वे अपने मनमाफिक न होने पर इसे अक्षम बताने लगते हैं। दरअसल, ट्रंप की कोशिश है कि उसकी मनमाफिक क्षेत्रीय शक्तियां और अमेरिका-संगठित पक्षों द्वारा शांति योजना को सिरे चढ़ाया जाए। निश्चित रूप से यह प्रयास सार्वभौमिक बहुपक्षवाद को नकार कर शासन व्यवस्था बदलने का प्रयास ही है। निर्विवाद रूप से जो शांति, बिना वैधता,सहमति और जवाबदेही के थोपी जाती है, वह कभी स्थायी समाधान का वाहक नहीं बन सकती है। ऐसे में किसी भी विश्वसनीय शांति प्रयास के जरिये उन वास्तविकताओं से निपटना होगा, जिन्हें ट्रंप मनमानी व जल्दबाजी में अकसर नजरअंदाज करते रहे हैं। अन्यथा यह कोशिश भी ट्रंप की अन्य कोशिशों की तरह विफल ही साबित होगी। आज गाजा संकट जिस मुश्किल दौर में पहुंच चुका है, उसके लिये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन, नागरिकों की सुरक्षा और समावेशी शासन का मार्ग प्रभावी समझौते से सुनिश्चित किया जाए। ऐसे हालात में यदि अमेरिका अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देता है या राजनीतिक अधिकारों के बजाय आर्थिक वादों को प्राथमिकता देता है, तो इस प्रयास में उस जोखिम की आशंका बनी रह सकती है, जो जमीनी वास्तविकताओं के बोझ से ढह सकता है। गाजा में शांति के लिये नये प्रयास कसौटी पर तभी खरे उतर सकते हैं जब इसमें गाजा की वास्तविक आवाज को सुना जाता हो। निश्चित रूप से हिंसा पर काबू पाना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन नागरिकों के जीवन की गरिमा बनाये रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। शांति समझौते में यदि स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी होती है तो यह शांति प्रस्ताव एक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि दशकों से हिंसा व विस्थापन का दंश झेल रहे गाजावासियों के कष्टों को और बढ़ाएगा ही। भारत को इस शांति प्रयासों में शामिल करने का प्रस्ताव अमेरिका की ओर से दिया गया है। भारत वहां सदा से ही द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता आया है। निर्विवाद रूप से भारत के जहां इस्राइल से बेहतर संबंध हैं, वहीं विश्वसनीयता अरब देशों में भी बरकरार रही है। गाजा में शांति प्रयासों में लगे अरब देशों के साथ भारत के मधुर संबंध रहे हैं।

विश्व को अस्थिर करता अमेरिका

(लेखक- किशन सनमुखदास भावनानीं)

- वेनेजुएला और ईरान के बाद अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर- नाटो की अग्निपरीक्षा और यूरोपीय एकता की निर्णायक जीत-एक समग्र विश्लेषण वैश्विक स्तरपर इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में जब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है,तब भी अमेरिका की विदेश नीति में एक पुराना साम्राज्यवादी आग्रह बार-बार उभरकर सामने आता है।अंतरराष्ट्रीय नियम-कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता के सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए सैन्य दबाव,आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अमेरिका की रणनीति का हिस्सा रहा है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिशें, ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति और अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के आक्रामक बयान,यह सब मिलकर एक ऐसे अमेरिका की तस्वीर पेश करते हैं जो वैश्विक स्थिरता का संरक्षक कम और अस्थिरता का कारक अधिक बनता जा रहा है।ग्रीनलैंड हमेशा डेनमार्क और यूरोपीय संप्रभुता का सवाल रहा हैं,ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है। इसका अर्थ यह है कि उसकी विदेश और रक्षा नीति डेनमार्क तथा यूरोपीय ढांचे से जुड़ी हुई है।जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे या उसे खरीदने जैसी बातों को सार्वजनिक मंच से दोहराया, तो यह केवल डेनमार्क ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की संप्रभुता को चुनौती देने जैसा था।यूरोपीय देशों को यह एहसास हुआ कि यदि आज ग्रीनलैंड पर दबाव डाला गया, तो कल किसी और यूरोपीय क्षेत्र पर भी ऐसा ही प्रयास हो सकता है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर यूरोप ने असामान्य रूप से एकजुट रुख अपनाया।ग्रीनलैंड का मामला नाटो के लिए भी एक निर्णायक परीक्षा बन गया। नाटो एक ऐसा सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि जब गठबंधन का सबसे शक्तिशाली सदस्य ही अपने सहयोगी देशों पर दबाव डालने लगे तो नाटो की नैतिकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।यूरोपीय देशों ने स्पष्ट संकेत दिया कि नाटो का मतलब केवल अमेरिकी हितों की रक्षा नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।इस एकजुटता ने ट्रंप प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक कदम उठाना आसान नहीं होगा। वेनेजुएला और ईरान के मामलों में जहां अमेरिका को सीमित विरोध का सामना करना पड़ा था, वहीं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप एक स्वर में खड़ा दिखाई दिया। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम सभी ने इस बात को स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का दबाव अस्वीकार्य है।यूरोपीय एकता ने ट्रंप के उस आत्मविश्वास को झटका दिया, जिसके तहत वे मानते थे कि आर्थिक या सैन्य दबाव डालकर किसी भी देश को झुकाया जा सकता है।

साथियों बात कर हम वेनेजुएला और ईरान- हस्तक्षेप की पुरानी पटकथा को समझने की करें तो ग्रीनलैंड से पहले अमेरिका की नजर वेनेजुएला और ईरान पर रही है।वेनेजुएला में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने,राष्ट्रपति को अपदस्थ करने और कथित अपहरण जैसी घटनाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा हुई। यह सब अंतरराष्ट्रीय कानूनों और किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में गैर- हस्तक्षेप के सिद्धांत के सीधे उल्लंघन थे।इसी तरह ईरान के खिलाफ लगातार प्रतिबंध, सैन्य धमकियां और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने की नीति ने मध्य-पूर्व को लंबे समय तक संघर्ष के दलदल में धकेल दिया।इन दोनों उदाहरणों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति कूटनीति पहले नहीं, बल्कि दबाव पहले की अवधारणा पर आधारित थी। ग्रीनलैंड- बर्फ से ढका द्वीप, लेकिन भू-राजनीति का गर्म केंद्र रहा।

साथियों बात अगर हम ग्रीनलैंड मुद्दे को समझने की करें तो यह भले ही जनसंख्या की दृष्टि से छोटा और भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्र हो,लेकिन उसकी रणनीतिक अहमियत असाधारण है।यह दुनियाँ का सबसे बड़ा द्वीप है और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण सैन्य,ऊर्जा, खनिज और वैश्विक व्यापार मार्गों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है।जलवायु परिवर्तन और बर्फ के पिघलने के साथ आर्कटिक में नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, जिससे यूरोप- एशिया-अमेरिका के बीच व्यापारिक दूरी कम हो सकती है। इसके साथ ही दुर्लभ खनिज, तेल और गैस जैसे संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड अब केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक शक्ति-राजनीति का केंद्र बन चुका है।

साथियों बात अगर कर हम अमेरिका की मंशा-आर्कटिक में वर्चस्व की होड़ को समझने की करें तो अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। वहां पहले से मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और रडार सिस्टम इस बात का संकेत हैं कि वॉशिंगटन आर्कटिक को केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि सामरिक युद्धक्षेत्र के रूप में देखता है।हालिया घटनाक्रम में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य और रणनीतिक गतिविधियां तेज करने के संकेत दिए। आधिकारिक तर्क यह दिया गया कि रूस और चीन जैसी उभरती ताकतों को संतुलित करने के लिए यह जरूरी है। लेकिन यूरोप ने इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह संतुलन नहीं बल्कि प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश अधिक प्रतीत हुई।

साथियों बात अगर हम टैरिफ हथियार--कूटनीति की जगह आर्थिक धमकी इसको समझने की करें तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर विरोध बढ़ता देख ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।घोषणा की गई कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।यह कदम स्पष्ट रूप से राजनीतिक दबाव बनाने के लिए था, ताकि यूरोपीय देश अमेरिका के रुख का समर्थन करने को मजबूर हों। हालांकि, इस बार यह रणनीति उलटी पड़ती नजर आई।,यूरोपीय संसद के सबसे बड़े राजनीतिक समूह ईपीपी के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दबाव और टैरिफ धमकियों से यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौतों की आत्मा पर सवाल खड़े हो गए हैं।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में अमेरिकी उत्पादों पर शून्य प्रतिशत टैरिफ की योजना को फिलहाल रोकना पड़ेगा।

क्या है कृष्णकर्म?

ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो। कोई भले ही कितने ही कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में मस्त है, तो उसे इस व्यापार को कृष्णभावनामृत में परिणत करने के लिए, कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे, तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्णकर्म है। अपनी इंद्रियतृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर, वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चाविग्रह स्थापित कर सकता है। यह सब कृष्णकर्म है।

मनुष्य को अपने कर्मफल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चाविग्रह स्थापित कराता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं होती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्णभावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण-मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्णकर्म है। मत्परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परमलक्ष्य, भगवान कृष्ण के परमधाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं।

विचार मंथन

अमेरिका और विश्व में अलग- थलग पडे ट्रंप, गैंगस्टर की छवि?

(लेखक-सनत जैन)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि सारी दुनिया में एक गैंगस्टर के रूप में बन रही है। जो अपनी सत्ता और ताकत के बल पर सारी दुनिया के देशों में कब्जा करना चाहते हैं। वह दादागिरी के बल पर शांति के मसीहा बनना चाहते हैं। ट्रंप को लगता है, उनके पास ईश्वरी शक्तियां आ गई हैं। वह जो चाहे वह कर सकते हैं। वह अमेरिका के संविधान में संशोधन कर तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में वह अपने परिवार के लोगों को सारी दुनिया के देशों में स्थापित करने की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी नीतियों के कारण अमेरिका और विश्व में उनका विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर जो अभियान छेड़ा है, उसे लेकर यूरोपीय और अन्य देशों पर जिस तरह का टैरिफ लगाया गया है, उसके कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का दूसरा वर्ष शुरू हो गया है। जब से वह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं सारी दुनिया के देशों को टैरिफ के नाम पर वह धमका रहे हैं। दुनिया के 91 देशों के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ की तलवार लटका रखी है। अमेरिका में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ईरान में अमेरिका को कड़ा झटका लगा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का जिस तरह से अपहरण कर अमेरिका की जेल में बंद करके रखा गया है, उससे ट्रंप और अमेरिका की साख सारी दुनिया में गिर गई है। ग्रीनलैंड में कब्जे और यूक्रेन को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों को अपने निशाने पर लिया है, उसके बाद अमेरिका का विरोध यूरोप के देशों में बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई के कारण ट्रंप अपने ही देश में अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। हाल ही में हुए सर्वे में 58 फीसदी अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप की नीतियों को अमेरिका के खिलाफ बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप के कई फैसलों पर अमेरिका की विभिन्न कोर्टों ने रोक लगा दी है। एजुकेशन, क्लीन एनर्जी और ग्रीन ट्रांजैक्शन से जुड़ी सहायता को अमेरिका ने रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय विदेशी सहायता कार्यक्रम को रोक दिया है। यहां तक की वैश्विक संस्थाओं को अमेरिका द्वारा जो सहायता दी जा रही थी। उसको रोककर संस्थाओं से अलग होने की नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का विरोध सारी दुनिया के देशों में बढ़ता जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ, इमीग्रेशन, रक्षा और एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरह से यूरोपीय और नाटो देशों को नाराज किया है। इसका असर नवंबर माह में होने वाले मिड टर्म चुनाव में देखने को मिल सकता है। सर्वे के अनुसार ट्रंप संसद में अपना बहुमत खो सकते हैं। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है। ट्रंप मिड टर्म चुनाव को टाल भी सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय और नाटो देशों के साथ जिस तरह से टकराव पैदा कर रहे हैं। उसको देखते हुए आगामी महीने डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी उथल-पुथल वाले साबित हो सकते हैं। अमेरिका की अभी तक जो वैश्विक छवि बनी हुई थी, उसमें तेजी के साथ दरार बढ़ती चली जा रही है। वैश्विक व्यापार संगठन की उपेक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डब्ल्यूएचओ और अन्य संस्थाओं से जिस तरह की दूरी डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। उससे स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप से जिन कारणों से युद्ध की शुरुआत हुई थी ठीक उसी तरह की स्थिति एक बार फिर बनना शुरू हो गई है। ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावना भी बनने लगी है। इस बात की आशंका आर्थिक विशेषज्ञ जता रहे हैं। ट्रंप की वर्तमान नीतियों से अमेरिका ठीक उसी राह पर चल पड़ा है, जैसे कभी सोवियत रूस चला था। जिसके कारण सोवियत रूस का विघटन हुआ। अमेरिका का जो वैश्विक वर्चस्व था, उसको बड़े पैमाने पर चुनौती मिल रही है। इस चुनौती का सामना किस तरह ट्रंप और अमेरिका करेगा, इसके लिए समय का इंतजार करना होगा।

चांदी 3.13 लाख के पार नए शिखर पर, सोने ने भी बनाया रिकॉर्ड

- सुरक्षित निवेश की बढ़ी मांग, टैरिफ धमकियों से बाजार में तेजी

नई दिल्ली ।

सोने और चांदी के वायदा कारोबार में लगातार रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और अमेरिका की ओर से नए टैरिफ लगाने की धमकी के चलते मंगलवार को लगातार दूसरे दिन दोनों कीमती धातुओं के भाव सार्वजे निक उच्च स्तर पर पहुंच गए। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय–दोनों ही बाजारों में तेजी का माहौल बना हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के बेंचमार्क फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत मजबूती के साथ हुई।

यह 141 रुपये की तेजी के साथ 1,45,775 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,45,629 रुपये था। इस समय सोना 621 रुपये की तेजी के साथ 1,46,260 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान सोने ने 1,46,567 रुपये का दिन का उच्चतम स्तर छूकर नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि दिन का निचला स्तर 1,45,500 रुपये रहा। एमसीएक्स पर चांदी के बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत सुस्त रही। यह 3,776 रुपये की गिरावट के साथ 3,06,499 रुपये प्रति किलो पर खुला।

हालांकि बाद में बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इस समय चांदी 1,241 रुपये की बढ़त के साथ 3,11,516 रुपये पर कारोबार कर रही थी। कारोबार के दौरान चांदी ने 3,13,896 रुपये प्रति किलो का अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना 4,633.70 डॉलर प्रति औंस पर खुलने के बाद 76.10 डॉलर की तेजी के साथ 4,671.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इस साल सोने ने 4,698 डॉलर प्रति औंस का उच्चतम स्तर छुआ। वहीं कॉमेक्स पर चांदी 90.60 डॉलर प्रति औंस पर खुली और बढ़त के साथ 93.18 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इस साल चांदी ने 94.74 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया है।

अटकलों से न्यू टाटा पंच के टेस्ट पर खड़े होने लगे सवाल

नई दिल्ली ।

भारत एनसीएपी में टाटा मोटर्स की न्यू पंच फेसलिफ्ट को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने के बाद इसके क्रैश टेस्ट वीडियो पर सवाल खडे होने लगे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया था। तमाम चर्चाओं के बीच टाटा मोटर्स ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ की है। कंपनी ने बताया कि यह भ्रम वीडियो में हुई एक 'एडिटिंग एरर' की वजह से पैदा हुआ है। टाटा के अनुसार, क्रैश टेस्ट के दौरान केवल एक ही नई पंच फेसलिफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। इस टेस्ट में माइक्रो-एसयूवी को खड़े टाटा एलपीटी ट्रक से सीधे टकराया गया और कोई अंडर-रन नहीं हुआ। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि टक्कर के बाद पंच का स्ट्रक्चर और बॉडी शेल पूरी तरह सुरक्षित रहा और अंदर बैठे यात्रियों को कोई खतरा नहीं हुआ। टाटा मोटर्स पहले भी रियल-वर्ल्ड क्रैश टेस्टिंग के लिए जानी जाती रही है। इससे पहले सिएरा कॉन्सेप्ट के साथ इस तरह की टेस्टिंग दिखाई गई थी और पंच के साथ इसे आगे बढ़ाया गया। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई टाटा पंच में 6 एयरबैग, ईएससी, एबीएस, टीपीएमएस, 360-डिग्री कैमरा और इसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यही वजह है कि पंच साल 2026 में भारत एनसीएपी की 5-स्टार रेटिंग पाने वाली पहली कार बन गई है। मालूम हो कि न्यू टाटा पंच के लॉन्च इवेंट के दौरान दिखाए गए इस वीडियो में पंच को एक खड़े ट्रक से टकराते हुए दिखाया गया था। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद कुछ दर्शकों ने फुटेज में दिख रही विसंगतियों को लेकर सवाल उठाए, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई। दरअसल, वीडियो के कुछ फ्रेम्स में ड्राइवर साइड के फ्रंट फेंडर और डोर के पास डेंट नजर आता है, जबकि अगले फ्रेम्स में वही हिस्सा बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। इस बदलाव ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद क्रैश टेस्ट के लिए एक से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी अटकलों से टेस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे।

स्विगी का फोकस भारत में विस्तार पर, वैश्विक योजना फिलहाल नहीं

- कंपनी का खाद्य क्षेत्र में सालाना 18-20 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य

नई दिल्ली । स्विगी फूड मार्केटप्लेस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में अभी भी 85-90 प्रतिशत खाद्य वितरण बाजार अप्रयुक्त है। केवल 10-12 प्रतिशत आबादी ने ऑनलाइन खाद्य आपूर्ति का उपयोग किया है, जिससे देश में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। अवसर सिर्फ खाद्य क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई अन्य व्यवसायों में भी मौजूद हैं। कंपनी खाद्य क्षेत्र में सालाना 18-20 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है। पिछले तिमाही के आंकड़े भी इसी रुझान की पुष्टि करते हैं। स्विगी कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग करके प्रबंधन, डिलीवरी पार्टनर और रेस्तरां साझेदारों को वास्तविक समय की जानकारी देती है। ग्राहक सेवा कॉल्स का विश्लेषण, व्यंजन बिक्री का डेटा और डिलीवरी की अधिकतम संभावना वाले क्षेत्र एआई के माध्यम से तुरंत साझा किए जाते हैं। उन्होने कहा कि फिलहाल कंपनी का ध्यान केवल घरेलू बाजार पर है और वैश्विक विस्तार की कोई योजना नहीं है। उनका मानना है कि भारत में खाद्य वितरण और पूरे खाद्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार और उद्योग को मिलकर काम करना होगा।

नए लहसुन की आवक बढ़ी, दिसंबर के बाद से तेजी का रुख

नीमच। बारिश के बाद लहसुन के भावों में लगातार मंदी रही, लेकिन दिसंबर के बाद से बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के बाद सोमवार को कृषि मंडी खुलते ही नए लहसुन की अच्छी आवक हुई, जिससे भावों में उछाल आया। अधिकतम भाव 2979 रुपए बढ़कर 17,500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया। मॉडल भाव 1400 रुपए की तेजी के साथ 8400 रुपए रहा। न्यूनतम भाव 390 रुपए घटकर 3501 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसानों का कहना है कि लागत के मुताबिक भाव नहीं मिल रहे हैं, जबकि व्यापारियों के मुताबिक बेहतर क्वालिटी आने पर दाम और बढ़ सकते हैं।

भारत में महंगे होंगे इलेक्ट्रिक वाहन

नई दिल्ली । चीन ने अपनी लिथियम-आयन बैटरियों पर एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट को 9 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसके अलावा अगले एक साल में इस प्रोत्साहन को पूरी तरह खत्म करने की योजना है। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की कुल निर्माण लागत में बैटरी का हिस्सा लगभग 33 फीसदी होता है। रिबेट में कटौती के कारण बैटरी की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे ईवी की कुल कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। इस समय लिथियम की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से बढ़ रही हैं, जिससे बैटरी की लागत और महंगी हो सकती है। बैटरी की कीमत बढ़ने से ईवी निर्माताओं के मार्जिन पर दबाव पड़ेगा।

उड़ान योजना को नई रफ्तार देने की तैयारी

- सब्सिडी मॉडल में बदलाव का प्रस्ताव

नई दिल्ली । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) को अधिक प्रभावी और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए एक नई फंडिंग व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। विभिन्न मंत्रालयों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद इस संबंध में एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे अब केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। सरकार का मानना है कि नई फंडिंग व्यवस्था लागू होने से दूर-दराज और कम विकसित क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा और आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ बनेगी। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना का उद्देश्य कम किराए में क्षेत्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना था। अब तक इस योजना के तहत 4,352 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है, जबकि हवाई अड्डों के विकास और बुनियादी ढांचे पर 4,638 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि, भारी निवेश के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। स्वीकृत 649 मार्गों में से फिलहाल केवल 60 प्रतिशत मार्ग ही संचालित हो रहे हैं। बढ़ती परिचालन लागत, सीमित किराया व्यवस्था, महंगा विमान ईंधन और कई रूट्स पर कम यात्री संख्या के कारण कई एयरलाइनों ने उड़ानें बंद कर दी हैं। वर्तमान सब्सिडी मॉडल में असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार अब नए समाधान की ओर बढ़ रही है।

भारत 2030 तक उच्च-मध्यम आय वाला देश बन सकता है- एसबीआई रिपोर्ट

- भारत 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर

मुंबई ।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 4,000 डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे वह उच्च-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। आजादी के बाद भारत को निम्न-मध्यम आय श्रेणी से बाहर निकलने में करीब 60 साल लगे। 1962 में प्रति व्यक्ति जीएनआई 90 डॉलर थी, जो 2026 तक 3,000 डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाकर जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर होगा। भारत को 2047 तक उच्च-आय वाला देश बनने के लिए प्रति व्यक्ति जीएनआई में 7.5 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना जरूरी है। 2001-2024 के बीच यह दर 8.3 फीसदी रही। रिपोर्ट में आर्थिक सुधारों की गति बनाए रखने और जीडीपी में 11-11.5 फीसदी की औसत वृद्धि बनाए रखने पर जोर दिया गया है, ताकि भारत 2030 तक उच्च-मध्यम आय और 2047 तक उच्च-आय देश बन सके।

शेयर बाजार भारी गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 1065 अंक, निफ्टी 353.00 अंक गिरा

10.12 लाख करोड़ का हुआ नुकसान

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1065.71 अंक नीचे आकर 82,180.47 अंकों पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 353.00 अंक की गिरावट के साथ ही 25,232.50 अंकों पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट ग्रीनलैंड मामले को लेकर अमेरिका की टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद विदेशी निवेशकों के सतर्कता बरतने से आई है। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स की केवल 1 कंपनी एचडीएफसी बैंक का शेयर ही बढ़त पर बंद हुआ। वहीं अन्य शेयरों में गिरावट रही। इसी प्रकार, निफ्टी केवल 3 कंपनियों के शेयर ही बढ़त पर बंद हुए। वहीं अन्य शेयरों में गिरावट रही। एचडीएफसी बैंक 0.38 फीसदी उछलकर जबकि जबकि एटरनल के शेयर आज सबसे ज्यादा 4.02 फीसदी की भारी गिरावट रही।आज एचडीएफसी बैंक को छोड़कर सेंसेक्स की बाकी सभी 29 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

सोमवार को बीएसई बाजार पूंजीकरण 465.68 लाख करोड़ रुपये था पर ये मंगलवार को 455.72 लाख करोड़ रुपये पर ही रह गया। इस प्रकार निवेशकों के 10.12 लाख करोड़ रुपये डूब गये

आज फाइनेंस, ऑटो, मेटल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खासतौर पर ज्यादा दबाव देखने को मिला। केवल बैंकिंग शेयरों में सीमित मजबूती रही। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान में रहा।. इसके अलावा ऑटो और आईटी शेयरों में भी दो फीसदी से ज्यादा की गिरावट रही। व्यापक बाजार में गिरावट और गहरी रही, जहां मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में करीब तीन फीसदी तक की कमजोरी देखी गई। बाजार जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और व्यापारिक तनावों के कारण बाजार में निकासी हावी रही। अमेरिका के यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते मतभेदों से दुनिया भर के बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है जिससे भारतीय बाजार पर भी दबाव आया है। इसके अलावा अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता से भी बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। डॉलर के मजबूत होने और रुपये के कमजोर होने से भी बाजारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

इससे पहले आज सुबह बाजार सपाट खुले। सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 83,207 अंक पर खुला। इसी तरह एनएसई का निफ्टी-50 25,580 पर लगभग सपाट खुलकर 23.55 अंक की कमजोरी के साथ 25,561 पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट का रुख बना रहा। जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी प्रमुख रूप से दबाव में रहे। जापान के बाजारों पर अतिरिक्त दबाव इसलिए भी देखा गया क्योंकि प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अगले महीने जल्द चुनाव कराने की आधिकारिक घोषणा की है। वहीं सोमवार को के चलते वॉल स्ट्रीट बंद रहा, जिससे वैश्विक संकेत सीमित रहे।

भविष्य में अंतरिक्ष में डेटा सेंटर और एआई से बदलेंगे जीवन के तरीके: सिस्को

दावोस । सिस्को के एक अधिकारी ने कहा है कि कृत्रिम मेधा (एआई) और उन्नत कंप्यूटिंग के कारण डेटा केंद्रों की बढ़ती मांग के चलते भविष्य में अंतरिक्ष में डेटा सेंटर विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर शीतलन और बिजली जैसी बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को देखते हुए अंतरिक्ष डेटा सेंटर एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा की तीव्रता पृथ्वी की तुलना में अधिक है, जिससे शीतलन लागत और ऊर्जा की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। डेटा सेंटरों में शीतलन अवसंरचना का वजन लगभग 90 प्रतिशत होता है। इस वजह से ऊर्जा कुशल या हरित डेटा सेंटर भविष्य में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अे धिकारी का कहना है कि ऊर्जा की उपलब्धता और शीतलन लागत के दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में डेटा सेंटर विकसित करना एक आर्थिक और तकनीकी रूप से उपयुक्त विकल्प हो सकता है। उन्होंने कृत्रिम मेधा को मानव इतिहास में सबसे बड़े वैश्विक बदलाव के रूप में देखा। उनका मानना है कि एआई हर नौकरी और कार्यप्रवाह को प्रभावित करेगा। हालांकि, लोग आमतौर पर अल्पकालिक प्रभाव को अधिक और दीर्घकालिक प्रभाव को कम आंकते हैं।

2025 में अरबपतियों की संख्या 3,000 के पार, संपत्ति 18.3 ट्रिलियन डॉलर पर

- एआई बूम और शेयर बाजार की तेजी से अमीर और अमीर, संपत्ति का केंद्रीकरण रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली ।

साल 2025 में दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या पहली बार 3,000 के आंकड़े को पार कर गई है। ऑक्सफैम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अरबपतियों की कुल संपत्ति बढ़कर 18.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह रिपोर्ट दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ठीक पहले जारी की गई है।` रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में अरबपतियों की संपत्ति में 16 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2020 की तुलना में यह बढ़ोतरी 81 फीसदी रही है, यानी करीब 8.2 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ नवंबर 2024 के बाद एक साल में संपत्ति की ग्रोथ 16.2 फीसदी रही, जो महामारी के बाद की औसत वृद्धि से लगभग तीन गुना अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनियों के बढ़ते वैल्यूएशन ने अमीरों की दौलत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका के अरबपतियों की संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ी है, हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। फोर्ब्स की रियल-टाइम लिस्ट के मुताबिक, एलन मस्क 779.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। स्पेसएक्स के संभावित आईपीओ और टेस्ला के शेयरों में मजबूती से उनकी दौलत में तेज उछाल आया। भारत में मुकेश अंबानी 104.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर बने हुए हैं, जबकि गौतम अडानी 89.6 अरब डॉलर और सावित्री जिंदल 40.2 अरब डॉलर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। दुनिया में संपत्ति का केंद्रीकरण अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 12 सबसे अमीर लोगों के पास उतनी ही दौलत है जितनी दुनिया की आधी आबादी के पास भी नहीं, जिससे वैश्विक आर्थिक असमानता पर चिंता बढ़ गई है।

डब्ल्यूईएफ में विशेषज्ञ बोले- एआई अपनाने में भारत सही दिशा में

– एआई सिर्फ तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि देशों और कंपनियों के भविष्य की रणनीति बन गया है

नई दिल्ली ।

दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पहले दिन आयोजित सत्र में विशेषज्ञों ने कहा कि एआई अब सिर्फ तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि देशों और कंपनियों के भविष्य की रणनीति बन गया है। गूगल की मूनशॉट इकाई सैंडबॉक्सएक्यू के सीईओ जैक हिडारी ने स्पष्ट किया कि अब या तो व्यक्ति, कंपनियां और सरकारें एआई के साथ आगे बढ़ेंगी, या अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार रहें। जैक हिडारी ने कहा कि भारत एआई अपनाने में सही रास्ते पर है और इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद मिल रही है।

उन्होंने शिक्षा क्षेत्र पर जोर दिया और कहा कि यदि भारत एआई को शिक्षा में नहीं अपनाता है, तो यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकता है। सेवलाइफ फाउंडेशन के सीईओ ने बताया कि एआई केवल डिजिटल कंटेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सड़क हादसों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें रोकने में भी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा कानूनों में सांस्कृतिक सहानुभूति शामिल करना जरूरी है और भारत का मेक इन इंडिया मॉडल विकासशील देशों में अपनाया जा सकता है। भारतीय आईटी कंपनी टेक महिंद्रा को भी एएमडी, सीमेंस और पेप्सिको जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ वास्तविक दुनिया में एआई अपनाने वाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। डब्ल्यूईएफ और एक्सेंचर की रिपोर्ट में एमआईएनडीएस संगठनों का जिक्र किया गया। टेक महिंद्रा को सामाजिक और सार्वजनिक हित के क्षेत्र में एआई के योगदान के लिए सूची में जगह मिली।

एसईजेड नियमों में बदलाव पर जोर, ट्रंप शुल्क के प्रभाव को कम करने की तैयारी

नई दिल्ली ।

वाणिज्य विभाग विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियमों में बड़े सुधार लाने पर जोर दे रहा है। यह कदम मुख्य रूप से अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 फीसदी तक के भारी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। अगर प्रस्तावित बदलाव लागू हो गए तो भारत की एसईजेड इकाइयों के लिए घरेलू बाजार में सामान बेचने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। इसके तहत वे घरेलू सेवाओं के लिए रुपये में भुगतान प्राप्त कर सकेंगी और अनुपालन मानदंडों को सरल बनाया जा सकेगा। एसईजेड को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून लगभग दो दशक पुराने हैं। पिछले चार साल से उनके सुधार पर चर्चा जारी है। कुछ बदलावों के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 में संशोधन की जरूरत होगी, जबकि अन्य सुधार केवल नियमों में बदलाव कर लागू किए जा सकते हैं। प्रस्तावों का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि इन सुधारों को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल किया जाए या नहीं। भारत में मौजूद एसईजेड इकाइयों का एक तिहाई से अधिक निर्यात अमेरिका को होता है। निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) के अनुसार, सितंबर में अमेरिका को निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 12 फीसदी घटकर

5.46 अरब डॉलर रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि एसईजेड नियमों में बदलाव से अमेरिका के अतिरिक्त शुल्कों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और इकाइयों के संचालन में निश्चितता आएगी।

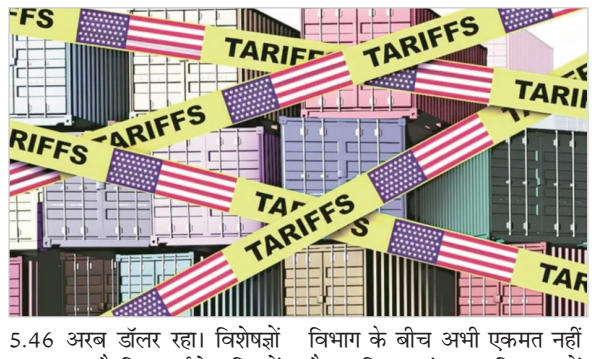

हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के बीच अभी एकमत नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास में वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम कर रहा है। बदलावों का उद्देश्य न केवल निर्यात को राहत देना है, बल्कि घरेलू बाजार में एसईजेड इकाइयों के लिए अधिक लचीलापन सुनिश्चित करना भी है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने लिया संन्यास

नई दिल्ली (एजेंसी)। अनुभवी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने खेल से संन्यास ले लिया है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइन ने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि अब उनकी फिटनेस पहले जैसी नहीं रही है। इसी कारण वह प्रतिस्पर्धी खेलों में अब नहीं उतरेंगी। साइना ने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने अंतिम बार कोई मुकाबला साल 2023 में सिंगापुर ओपन में खेला था। वह गत ढाई-तीन साल से पेशेवर बैडमिंटन से दूर रही हैं। उनके घुटने में भी समस्या है। इस कारण वह काफी समय से खेल से दूर चल रहीं थीं। उनकी उम्र भी 35 के करीब पहुंच रही है जिससे भी उनके खेल पर प्रभाव पड़ा है। उन्हें अपने योगदान के कारण अर्जुन पुरस्कार (2009), मेजर ध्यानचंद खेल रत्न (2010), पद्म श्री (2010) और पद्म भूषण (2016) जैसे अवार्ड मिले हैं।

साइना ने पिछले कुछ समय से बैडमिंटन नहीं खेला है और उसके बाद से ही उनके संन्यास की अटकलें लगायी जा रहीं थीं। साइना ने कहा, ''मैंने दो साल पहले ही खेलना छोड़ दिया था मैंने अपनी अनुसार ही खेला और अब संन्यास की घोषणा की है। साथ ही कहा कि अगर आप और खेलने में सक्षम नहीं हैं तो खेल में बने रहने का मतलब नहीं है।'' नेहवाल ने कहा कि यह फैसला उन्होंने घुटने की गंभीर समस्या से लिया, जिसकी वजह से लगातार उच्च दबाव वाली ट्रेनिंग कठिन हो गयी थी।

नेहवाल ने कहा, ÷ उनका घुटना दर्द कर रहा है। कार्टिलेज पूरी तरह से खराब हो गया है, इसके अलावा उन्हें जोड़ो की बिमारी है, यह बात मेरे माता-पिता को पता होनी चाहिए थी, मेरे कोच को यह जानना जरूरी था और मैंने बस उनसे कहा, 'अब शायद मैं यह और नहीं खेल पाऊंगी, यह कठिन है।÷ संन्यास की घोषणा पर साइना ने कहा, लोगों को धीरे-धीरे पता चल ही रहा था कि साइना नहीं खेल रही है। घुटने की चोट को लेकर साइना ने कहा, खेल में शीर्ष पर आने आठ से नौ घंटे ट्रेनिंग की जरुरी होती है पर अब मेरा घुटना एक या दो घंटे में ही दर्द करने लगा था।

गौरतलब है कि बैडमिंटन में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली साइना पहली भारतीय खिलाड़ी थीं। इसके अलावा वह साल 2015 में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी भी रही थीं। बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2008 में उन्होंने जीत हासिल की जबकि सुपर सीरीज खिताब 2009 इंडोनेशिया ओपन 2009 उन्होंने जीत हासिल की। 2010 और 2018 राष्ट्रमण्डल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। वह इन खेलों में दो एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।

तनावपूर्ण माहौल में खेले गए मैच में सेनेगल ने मोरक्को को हराकर जीता अफ्रीका कप

रबात (मोरक्को) (एजेंसी)। सेनेगल ने पेप गुये के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की मदद से मेजबान मोरक्को को 1-0 से हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। बेहद तनावपूर्ण परिस्थितियों में खेले गए फाइनल में दोनों टीम निर्धारित समय तक गोल नहीं कर पाई थी लेकिन आखिर में पेप गुये निर्णायक गोल करने में सफल रहे।

फाइनल मैच में तनाव काफी बढ़ गया था। मैच के दौरान ऐसा समय भी आया जब दर्शकों ने मैदान पर घुसने की कोशिश की। यही नहीं सेनेगल के खिलाड़ी दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम में पेनल्टी के फैसले के विरोध में मैदान से बाहर चले गए थे। यह स्पष्ट नहीं था कि खेल जारी रह पाएगा या नहीं क्योंकि प्रशंसक सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए थे। इसके कारण 14 मिनट तक खेल नहीं हो पाया था। खेल शुरू होने पर सेनेगल के एडुआर्ड मेंडी ने ब्राहिम डियाज़ की पेनल्टी को आसानी से बचा लिया। इसके बाद गुये ने अतिरिक्त समय के चौथे मिनट में विजयी गोल दागा। मोरक्को की पराजय के कारण 69,500 दर्शकों की क्षमता वाला प्रिंस मौले अब्देललाह स्टेडियम अंतिम सीटी बजते ही खाली होने लग गया था। सेनेगल के खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाते हुए देखने के लिए बहुत कम लोग बचे थे। सेनेगल ने दूसरी बार अफ्रीका कप जीता। इससे पहले वह 2021 में चैंपियन बना था।

केन्द्रीय अनुबंध में विराट, रोहित का डिमोशन तय, बी ग्रेड में रखे जाने की संभावना

इंदौर (एजेंसी)। मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के नये केन्द्रीय अनुबंध में अनुभवी खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा का डिमोशन होना तय है। अभी ये दोनो ही खिलाड़ी ए प्लस ग्रेड में

हैं। ये ग्रेड उन खिलाड़ियों को मिलता है जो तीनों ही प्रारुप खेलते हैं। विराट और रोहित अब केवल एकदिवसीय प्रारुप ही खेलते हैं। ऐसे में इनका डिमोशन तय है। इसका एक और कारण ये है कि बीसीसीआई अनुबंध से ए प्लस कैटेगरी को समाप्त कर उसकी जगह पर केवल ए, बी और सी कैटेगरी को जारी रख सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा का भी डिमोशन क्योंकि ये दोनो भी पिछली बार ए प्लस कैटेगरी में शामिल थे। बीसीसीआई को अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 तक के लिए केन्द्रीय अनुबंध की घोषणा करनी है। ऐलान बीसीसीआई को करना है।

एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई एक बदला हुआ केन्द्रीय अनुबंध सिस्टम लाने वाला है, जिसके तहत ग्रेड ए प्लस को बंद कर दिया जाएगा। इस नये सिस्टम को मंजूरी मिली तो विराट और रोहित को बी ग्रेड में रखा जाएगा। ये दोनो ही अभी तक ए प्लस कैटेगरी में थे। रविंद्र जडेजा का भी यही हाल होगा पर जसप्रीत बुमराह ए कैटेगरी में चले जाएंगे।

चयहन समिति ने अनुबंध प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। कमिटी ने 7 करोड़ राशि वाले ए प्लस वर्ग को समाप्त कर केवल तीन वर्ग ए, बी और सी रखने को कहा है। इससे वेतन पर भी प्रभाव पड़ेका। ए प्लस कैटेगरी के लिए पहले 7 करोड़ मिलते थे, ए के लिए 5, बी के लिए 3 और सी के लिए 1 करोड़ रुपये सालाना मिलते थे। अगर ये मॉडल अप्रूव हुआ तो केवल एकदिवसीय खेल रहे रोहित और विराट को बी कैटेगरी में रखा जाएगा।

आरसीबी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली टीम बनी

वडोदरा (एजेंसी)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में इतिहास रचते हुए गुजरात जायंट्स को 61 रनों से करारी शिकस्त दी और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। यह मुकाबला वडोदरा के कोटांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला गया। इस जीत के साथ RCB ने टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। गौतमी नाइक की संयमित अर्धशतकीय पारी और शानदार टीम प्रदर्शन के दम पर RCB इस सीजन नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई।

लगातार जीतों का रिकॉर्ड, WPL में पहली बार हुआ ऐसा

RCB की यह जीत सिर्फ प्लेऑफ टिकट तक सीमित नहीं रही। 2025 सीजन के अंत से लेकर मौजूदा सीजन तक RCB अब लगातार छह मुकाबले जीत चुकी है, जो WPL इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है।

अब तक: मुंबई इंडियंस ने दो बार लगातार 5 मैच जीते थे, RCB ने पहले भी एक बार 5 मैचों की जीत दर्ज की थी, दिल्ली कैपिटल्स का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 लगातार जीत रहा है; लेकिन स्मृति मंधाना की कप्तानी में RCB WPL के चार साल के इतिहास में लगातार छह जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई है।

दिल्ली के खिलाफ नजर सातवीं जीत पर

अगर RCB 24 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स को हरा देती है, तो वह: WPL सीजन की शुरुआत में लगातार 6 जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बनेगी, कुल मिलाकर जीतों की संख्या 7 तक पहुंच जाएगी, फिलहाल, सिर्फ मुंबई इंडियंस ही 2023 में सीजन की शुरुआत लगातार पांच जीत के साथ कर पाई थी।

कैसे RCB ने गुजरात जायंट्स को दी मात

टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी RCB की शुरुआत खराब रही। शुरुआती दो ओवरों में ही ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया वोल आउट हो गईं और टीम का स्कोर 9/2 हो गया।

इसके बादः गौतमी नाइक ने मोर्चा संभाला, कप्तान स्मृति मंधाना के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 60 रनों की अहम साझेदारी की, मंधाना 26 रन बनाकर ऐश्ले गार्डनर की गेंद पर LBW आउट हुई। नाइक की जिम्मेदार पारी की बदौलत RCB ने मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद गेंदबाज़ों ने गुजरात को पूरी तरह दबाव में रखा और 61 रन से बड़ी जीत दर्ज की।

आईपीएल की तरह ही पीएसएल में भी होगी खिलाड़ियों की नीलामी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर ही खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित करेगा। पीसीबी इस साल अपने 11 वें सत्र से पहले ये बदलाव करेगा। इसके तहत ही अब तक जारी प्लेयर ड्राफ्ट प्रणाली की जगह प्लेयर नीलामी मॉडल रखा जाएगा। पीसीबी का कहना है कि वह विकास , प्रतिस्पर्धा के साथ ही नये तरीके अपननो पर जोर दे रहा है। जिससे कि टूर्नामेंट का आकर्षण बढ़ सके। पीसीबी ने कहा कि बदलाव का लक्ष्य खेल में पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ ही खिलाड़ियों को कमाई के अधिक अवसर देना है में नए नियमों के अनुसार हर फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा चार खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, जिसमें हर वर्ग से एक खिलाड़ी शामिल होगा। वहीं पहले हर फ्रेंचाइजी को अपनी टीम से 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति थी जिसमें एक मेंटर, एक ब्रांड एंबेसडर और प्लेयर ड्राफ्ट में नौवें खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए राइट टू मैच विकल्प शामिल था। पीएसएल 11 के लिए मेंटर, ब्रांड एंबेसडर और आरटीएम से जुड़े नियम हटा दिए गए हैं। नई शामिल होने वाली टीमों को प्लेयर नीलामी से पहले उपलब्ध प्लेयर पूल से चार खिलाड़ियों को चुनने और रिटेन करने की अनुमति होगी। हर फ्रेंचाइजी को एक विदेशी खिलाड़ी की सीधे शामिल करने की भी इजाजत होगी। जो पीएसएल 10 में नहीं खेला था जिससे टीमें नई अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा के साथ लाकर अपनी टीमों को मज़बूत कर सकेंगी। इसके अलावा खिलाड़ियों का वेतन बढ़ाकर प्रति फ्रेंचाइजी 16 लाख रुपये कर दिया गया है।

15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान के बीच होंगे दो क्रिकेट मुकाबले

- पुरुष टीमें टी20 विश्वकप, महिला टीमें एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबले में टकरायेंगी

मुम्बई । भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबलों का प्रशंसकों को इंतजार रहता है। इन मैचों में काफी रोमांच रहता है। अब एक बार फिर 15 फरवरी को होने वाले टी20 विश्वकप में दोनो ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। इस दिन दोनो ही टीमों के बीच एक नहीं दो मुकाबले होंगे क्योंकि इसी दिन दोनों देशों की पुरुष टीमों जहां टी20 विश्वकप, वहीं महिला टीमें एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में मुकाबला करेंगी। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी तक बैंकॉक, थाईलैंड में खेला जाएगा और इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें दो समूहों रखा गया है। इस टी20 टूर्नामेंट में एशिया की शीर्ष महिला क्रिकेटर नजर आयेंगी। इसमें चार सदस्य देशों की 'ए' टीमें और क्षेत्र की चार शीर्ष एसोसिएट टीमें भी शामिल रहेंगी। इसकें ग्रुप ए में भारत ए, पाकिस्तान ए, यूएई और नेपाल हैं। भारत ए टीम अपना अभियान 13 फरवरी को यूएई के खिलाफ शुरू करेगी। इसके बाद 15 फरवरी को पाकिस्तान ए से उसका मुकाबला होगा। वहीं टीम 17 फरवरी को नेपाल से खेलेगी। ग्रुप बी में श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए, मलेशिया और मेजबान थाईलैंड के बीच मुकाबला होगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय पुरुष टीम को टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप ए में पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका से खेलेगी। भारतीय टीम अपने विश्वकप अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ करेगी। वहीं 12 फरवरी को उसे नामीबिया, 15 फरवरी को पाकिस्तान और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से खेलना है।

मोहम्मद शमी ने एसआईआर सुनवाई पूरी की, कहा- यह ऐसी चीज नहीं जिससे आपको नुकसान होगा

कोलकाता (एजेंसी)। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मंगलवार को कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर से अपनी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सुनवाई पूरी करने के बाद कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या नहीं हुई। शमी ने नागरिकों से आगे आकर चल रही SIR प्रक्रिया में हिस्सा लेने का भी आग्रह किया और जोर देकर कहा कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।

शमी ने अपनी SIR सुनवाई के बाद पत्रकारों से कहा, 'कोई समस्या नहीं थी... स्ट्रक्चर ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको नुकसान होगा... जिनके पास SIR फॉर्म नहीं है, उन्हें भी आना चाहिए।' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शमी द्वारा भरे गए जनगणना

फॉर्म में कुछ जगहों पर गड़बड़ियां थीं, जिसके कारण उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शमी अपने क्रिकेट करियर के लिए पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। वह रणजी ट्रॉफी में बंगाल टीम का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) को पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान में 'लॉजिकल गड़बड़ियों' की श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल में स्ट्रक्चर प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक अवैधताओं का आरोप लगाने वाली विभिन्न याचिकाओं पर ECI को निर्देश जारी किए।

लेह में छठे खेलो इंडिया शीत खेलों की शुरूआत, आइस हॉकी सहित ये खेल भी होंगे शामिल

लेह । उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने अत्याधुनिक एनडीएस आइस हॉकी स्टेडियम पर छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की शुरूआत की मंगलवार को घोषणा की। खेल अगले सात दिन तक चलेंगे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इनका समापन होगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि 19 प्रदेशों के 1060 प्रतिभागी इन खेलों में भाग लेंगे जिनमें खिलाड़ी, तकनीकी अधिकारी, सहयोगी स्टाफ और वालिंटियर के साथ भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस शामिल है। उन्होंने कहा कि आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग के अलावा पहली बार फिगर स्केटिंग की स्पर्धायें भी होंगी। उद्घाटन समारोह में गुप्ता ने कहा कि लगातार तीसरे साल खेलों की मेजबानी से लद्दाख की क्षमता, प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण उच्च पर्वतीय हालात में बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी की तैयारियों पर देश का भरोसा झलकता है। उन्होंने खेलों के विकास के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एनडीएस आइस हॉकी रिंक, गुपुक तालाब और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर रिंक खेलों के लिये पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीएस स्टेडियम पर 53.58 करोड़ रूपए की लागत से आइस हॉकी रिंक बड़ी उपलब्धि है और कारगिल में एक और आइस हॉकी रिंक तैयार हो रही है जिससे लद्दाख में शीतकालीन खेलों का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा।

सूर्यकुमार पहले टी20 में कर सकते हैं अपने 9000 रन पूरे

नागपुर । भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच में 25 न बनाते ही अपने 9000 रन पूरे करे लेंगे। ये रन बनाते ही सूर्या 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन ने ही 9000 रन बनाये हैं। पिछले एक साल में सूर्यकुमार का टी20 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। वह अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाये। कप्तानी की जिम्मेदारी के कारण उनकी बल्लेबाज़ी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यूर्या ने अब तक 346 मैच में 8,975 रन बनाये हैं। उनका औसत 34.78 जबकि स्ट्राइक रेट 152 से अधिक है। उनके नाम 6 शतक और 59 अर्धशतक हैं। भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट के नाम है, जिन्होंने 414 मैचों में 13,543 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिनके खाते में 463 मैचों में 12,248 रन हैं। वहीं शिखर धवन के नाम 334 मैचों में 9,797 रन हैं और वह तीसरे नंबर पर हैं।

भारतीय टीम पहले टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी

नागपुर (एजेंसी)। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम बुधवार को यहां पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करने उतरेगी। भारतीय टीम का लक्ष्य इस सीरीज को जीतकर अगले माह होने वाली टी20 सीरीज के लिए लय हासिल करना रहेगा। भारतीय टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में टी20 में अच्छा रहा है पर सूर्यकुमार के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। ऐसे में सूर्यकुमार का लक्ष्य इस सीरीज में अधिक से अधिक रन बनाकर टी20 विश्वकप के लिए फार्म हासिल करना रहेगा। सूर्यकुमार ने साल 2024 में टी20 टीम की कप्तानी संभाली थी जिसके बाद से ही भारतीय टीम को अधिकतर मुकाबलों में जीत मिली है।

पिछले दो साल में भारतीय टी20 टीम को कुछ मुकाबलों में ही हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कीवी टीम के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में भी वह जीत की प्रबल दावेदार रहेगी। भारतीय टीम को हालांकि बल्लेबाजी तिलक वर्मा की कमी खेलेगी। तिलक सर्जरी के कारण इस इस मैच में नहीं खेलेंगी। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम भी काफी अच्छी है। इससे पहले हुई एकदिवसीय सीरीज में जीत से उसका मनोबल बढ़ा हुआ है जिसका लाभ उसे मिलेगा हालांकि उसकी राह इतनी आसान नहीं है। भारतीय टीम ने पिछले 25 में से 18 मैच जीते हैं। टीम के पास अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज और वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर है। वहीं न्यूजीलैंड ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद खेले गए 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से केवल 13 में जीत हासिल की है। उसके पास आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे हैं। टीम के पास कप्तान मिचेल सैंटनर जैसा स्पिनर और जैकब डफी जैसा तेज गेंदबाज है। अच्छी फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के रहने से टीम काफी मजबूत हुई है। तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क इस मैच में रहेंगे। इसका कारण है कि माइकल ब्रैसवेल और एडम मिल्ने दोनो ही फिट नहीं हैं।

वहीं भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या हैं। स्पिनर वरुण भारतीय टीम के मुख्य हथियार होंगे। वरुण के सातवें से 15वें ओवर के बीच के चार ओवर अक्सर मैच का रुख बदील देते हैं।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

भारतः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा।

न्यूजीलैंडः मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फाउल्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रैसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क।

सिनर ने खिताबी हैट्रिक अभियान की सकारात्मक शुरुआत की, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में बनाई जगह

मेलबन। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने अपने खिताब बचाने के अभियान की सकारात्मक शुरुआत करते हुए मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाई। सिनर ने रॉड लेवर एरिना पर सिर्फ तीन गेम गंवाए और एक घंटे से थोड़ा अधिक समय बिताकर खिताबी हैट्रिक पूरा करने के अपने अभियान की शुरुआत की। विश्व में दूसरे नंबर के खिलाड़ी सिनर जब 6-2, 6-1 से आगे चल रहे थे, तभी ह्यूगो गैस्टन ने अचानक एक अज्ञात चोट के कारण मैच से हटने का फैसला किया। सिनर ने कहा, 'मैंने देखा कि वह दूसरे सेट में बहुत तेज गति से सर्व नहीं कर रहा था लेकिन मैं इस तरह से मैच नहीं जीतना चाहता था।' सिनर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में लगातार तीन बार चैंपियन बनने वाले चौथे खिलाड़ी बनने की राह पर हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

दक्षिण अफ्रीका में 150 साल पुराने हिंदू मंदिर पर धोखाधड़ी के आरोप

डरबन , एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 150 साल से भी अधिक पुराना एक हिंदू मंदिर धोखाधड़ी के आरोपों से जूझ रहा है। मंदिर पर नगर निगम का पांच लाख रेंड लगभग 27.64 लाख रुपये का बिल भी बकाया है, जिसके कारण मंदिर की नागरिक सेवाओं के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण अफ्रीकी हिंदू महासभा समुदाय से 151 साल पुराने उम्बिलो श्री अम्बालावनार अलायम मंदिर को बचाने का आह्वान किया। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की स्थापना 1860 में भारत से डरबन गए गिरमिटिया मजदूरों ने की थी। यह दक्षिण अफ्रीका का पहला हिंदू मंदिर है। इसे 1980 में राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया गया था। मंदिर के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया में इस आर्थिक संकट की जानकारी देते हुए कहा, मंदिर के रखरखाव में भी दिक्कत आ रही है। मंदिर प्रबंधन पर दान की धनराशि निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करने के आरोप हैं। मंदिर के कार्यकारी प्रबंधन ने अब फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने का फैसला किया है। यह ऑडिट सभी वित्तीय लेनदेन, फंडिंग रिकॉर्ड और बताई गई विसंगतियों की जांच, सत्यापन और मिलान करेगा, जिसमें मौजूदा ऑडिटर की रिपोर्ट से संबंधित विसंगतियां भी शामिल हैं।

पाकिस्तान के छात्र समूहों का 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी एकजुटता मार्च का एलान

इस्लामाबाद , एजेंसी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के छात्र संगठनों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं और अन्य मुद्दों को उजागर करने के प्रयासों के तहत 12 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में छात्र एकजुटता मार्च की घोषणा की है। डॉन के अनुसार यह घोषणा लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के केंद्रीय महासचिव इकबाल खान, द स्टूडेंट्स हेराल्ड के मुख्य संपादक काजी शहरयार, पीएससी की प्रवक्ता सारा अली, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के सूचना सचिव शेर अली, पूर्व उपाध्यक्ष अली रजा और जेकेएनएसएफ नेता मुजीब अकबर उपस्थित थे। इन समूहों ने यह भी घोषणा की कि छात्रों की आत्महत्याओं और परिसरों में छात्रों की व्यापक चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी (जीसीयू) से पंजाब विधानसभा तक एक मार्च निकाला जाएगा।

पाकिस्तान : दिसंबर में 40 पर्यावरणीय नमूनों में पोलियो वायरस का पता लगाया

इस्लामाबाद , एजेंसी। डॉन ने इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) की पोलियो प्रयोगशाला के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि दिसंबर महीने के दौरान चारों प्रांतों और संघीय राजधानी से लिए गए 40 पर्यावरणीय नमूनों में पोलियो वायरस की पुष्टि हुई है। एनआईएच पोलियो प्रयोगशाला के अधिकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 में 87 जिलों से लिए गए 127 सीवेज नमूनों की पोलियो वायरस की उपस्थिति की जांच की गई। इनमें से 87 नमूनों की जांच नकारात्मक पाई गई, जबकि 40 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। बलूचिस्तान से कुल 23 नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 21 नकारात्मक और दो सकारात्मक पाए गए। खैबर पाकिस्तान से कुल 34 नमूने एकत्र किए गए , जिनमें से 26 नकारात्मक और आठ सकारात्मक पाए गए। पंजाब से 31 नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 25 नकारात्मक और छह सकारात्मक पाए गए। सिंध में छह नमूने नकारात्मक और 23 सकारात्मक पाए गए। इस्लामाबाद में पांच नमूनों में से एक सकारात्मक पाया गया।

वेनेजुएला से मचाडो की सुरक्षित निकासी, अमेरिकी मदद से नोबेल लेने नॉर्वे पहुंची थी

ओस्लो, एजेंसी। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो का अपने देश से सुरक्षित निकास का ड्रामाई वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखता है कि कैसे एक अमेरिकी टीम की मदद से उन्होंने खतरों से भरा सफर तय किया और नॉर्वे पहुंचीं। मारिया मचाडो दिसंबर में वेनेजुएला से निकलकर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो गई थीं, जहां उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार करना था। यह पुरस्कार उन्हें लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए उनके संघर्ष के लिए दिया गया था। वीडियो में दिखता है कि मचाडो कारिबियन सागर के किनारे एक छोटी नाव पर थीं, जहां उन्होंने अमेरिकी विशेष बल के अनुभवी सदस्य ब्रायन स्टर्न और उनकी टीम से मुलाकात की। इसके बाद वह दूसरी नाव में बैठती हैं और कैमरे से कहती हैं 'मैं मारिया कोरिना मचाडो हूं। मैं जीवित हूं, सुरक्षित हूं और ग्रे बुल टीम की मदद के लिए बेहद आभारी हूं। ग्रे बुल रेस्क्यू नाम की यह अमेरिकी टीम कई घंटों की कठिन नौकायन के बाद मचाडो को बचाकर सुरक्षित निकालने में सफल रही। इस राह में उन्होंने अंधेरे और खतरनाक समुद्री हवाओं का सामना भी किया। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला में चुनावों में भाग लेने से रोका गया था और उन्हें अपने देश में डर का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे लगभग एक साल तक गुप्त रूप से छिपी रहीं।

स्पेन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की जोरदार टक्कर, 21 लोगों की मौत और 75 घायल

कोर्डोबा, एजेंसी। स्पेन में भीषण रेल हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और 75 घायल हैं। कोर्डोबा के पास एडमुज गांव के नजदीक यह दुर्घटना हुई। मलागा से मैड्रिड जा रही निजी कंपनी इर्यो की हाई-स्पीड ट्रेन का पिछला हिस्सा अचानक पटरी से उतर गया। इसके बाद यह दूसरी दिशा से आ रही ट्रेन से टकरा गई। हादसा रविवार शाम 7:45 बजे हुआ, जिसमें पहली ट्रेन में लगभग 300 और दूसरी में 200 यात्री सवार थे। स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंटे ने मौतों की संख्या 21 बताई। उन्होंने कहा कि सभी जीवित बचे लोगों को निकाल लिया गया है, हालांकि कुछ और शव बाकी हो सकते हैं। आंदालूसिया के क्षेत्रीय अध्यक्ष जुआनमा मोरेनो ने बताया कि 75 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 15 की हालत गंभीर है। बचावकर्मी पूरी रात मलबे से शव निकालने में जुटे रहे। यह हादसा बेहद असामान्य बताया जा रहा है क्योंकि यह सपाट और हाल ही में मई में नवीनीकृत ट्रैक पर हुआ। पटरी से उतरने वाली ट्रेन चार साल से कम पुरानी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेनफे ट्रेन के पहले दो डिब्बे पटरी से उतरकर 4 मीटर नीचे ढलान पर जा गिरे, जिससे उसके आगे के हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा।

'ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो' : एक यात्री और पत्रकार साल्वाडोर जिमेनेज ने बताया कि क्षण भर में ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। यात्रियों ने इमरजेंसी हैमर से खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। घटनास्थल दूरदराज होने के कारण पहुंचना मुश्किल था, फिर भी स्थानीय लोग कंबल और पानी लेकर मदद के लिए पहुंचे। स्पेनिश सेना, रेड क्रॉस और अन्य एजेंसियों ने बचाव अभियान में हिस्सा लिया।

सदी का स्पेन का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा : स्पेन में यूरोप का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क है, जिसमें 3100 किलोमीटर से अधिक ट्रैक हैं। यह काफी सुरक्षित माना जाता है। 2024 में रेनफे की हाई-स्पीड ट्रेनों में 2.5 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, राजा फेलिप वीआई और रानी लेटिजिया ने शोक व्यक्त किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी संवेदना जताई। जांच में एक महीने तक लग सकता है। सोमवार को मैड्रिड और आंदालूसिया के बीच ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। यह इस सदी का स्पेन का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है।

यात्री बोले- भूंकप जैसा झटका लगा : रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। स्पेनिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर टीआरवीई के पत्रकार साल्वाडोर जिमेनेज भी इर्यो ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन के आखिरी दो डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से एक पूरी तरह पलट गया। जिमेनेज के मुताबिक, ट्रेन शाम 6:40 बजे समय पर मलागा से रवाना हुई थी। कुछ देर बाद अचानक जोरदार झटका लगा और ट्रेन पटरी से उतर गई। इसके बाद यात्रियों को हथौड़ों से खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया।

कई यात्रियों को खिड़कियों से बाहर निकलने के दौरान चोटें भी आईं। कुछ यात्रियों ने ट्रेन के अंदर धुआं भरने की भी शिकायत की।

मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच ट्रेन सर्विस सस्पेंड : स्पेन की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी एडीआईएफ ने बताया कि मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच सभी ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई हैं। मौके पर आपातकालीन सेवाएं तैनात हैं और राहत-बचाव कार्य रातभर जारी रहा। स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंटे ने कहा कि वह एडीआईएफ के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से हालात पर नजर रखे हुए हैं।? ??रेस्क्यू ऑपरेशन में स्पेन की सेना की इमरजेंसी यूनिट्स भी शामिल की गई हैं। रेड क्रॉस की टीमें घायलों के इलाज में स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद कर रही हैं। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया।

पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में चौंकाने वाला नतीजा

लिस्बन, एजेंसी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव में रविवार को चौंकाने वाले नतीजे में एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी के नेता दूसरे स्थान पर रहे। अगले महीने होने वाले दूसरे दौर के मतदान में उनका सामना एक मध्य-वामपंथी प्रतिद्वंद्वी से होगा, जो आधिकारिक नतीजों के अनुसार यूरोप की बढ़ती धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए एक और राजनीतिक सफलता ला सकता है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगभग 98 प्रतिशत वोटों की गिनती हो चुकी है। सात साल से भी कम समय पहले बनी चेगा पार्टी के नेता आंद्रे वेंचुरा को 24 प्रतिशत वोट मिले हैं। वह मध्य-वामपंथी समाजवादी उम्मीदवार एंटोनियो जोस सेगुरो से पीछे दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें लगभग 31 प्रतिशत वोट मिले। 8 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान में दोनों शीर्ष उम्मीदवारों का आमना-सामना होगा।

पुर्तगाल में वेंचुरा की पार्टी ने कैसे किया दमदार प्रदर्शन : आंद्रे वेंचुरा का दमदार प्रदर्शन यूरोप में धुर दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर हो रहे बदलाव में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। दरअसल, हाल के वर्षों में लोकलुभावन पार्टियों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली है या उसके करीब पहुंच गई हैं। जनता के भारी समर्थन के चलते चेगा पार्टी पिछले साल पुर्तगाल की संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि इसकी स्थापना को महज छह साल ही हुए थे। वेंचुरा और उनके समर्थकों को

यूरोप भर में जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और पड़ोसी देश स्पेन में समान विचारधारा वाली राष्ट्रवादी पार्टियों के बढ़ते प्रभाव से प्रोत्साहन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में अन्य नौ उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन कोई भी पहले दौर की जीत के लिए आवश्यक 50 प्रतिशत से अधिक वोटों के करीब नहीं पहुंच सका। चुनाव जीतने वाला राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की जगह लेंगे, जिन्होंने पांच-पांच साल के दो कार्यकाल की सीमा पूरी कर ली है।

अप्रवासियों के खिलाफ वेंचुरा का चुनाव प्रचार : वेंचुरा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान हाल के वर्षों में पुर्तगाल में विदेशी कामगारों की उपस्थिति को लेकर मुखरता से आवाज उठाई है। उनका कहना है कि पुर्तगाल हमारा है। चुनाव प्रचार के दौरान वेंचुरा ने पूरे देश में बिलबोर्ड लगवाए जिन पर लिखा था, 'यह बांग्लादेश नहीं है और प्रवासियों को कल्याणकारी योजनाओं पर जीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' पुर्तगाल में कुछ साल पहले तक सार्वजनिक रूप से इस तरह अप्रवासी-विरोधी भावना जताना अकल्पनीय था।

मध्य अमेरिकी देश में गैंगवार से दहशत, जेल में हिंसा के बाद सात पुलिसकर्मियों की हत्या

ग्वाटेमाला सिटी , एजेंसी। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में गैंग हिंसा ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। राजधानी ग्वाटेमाला सिटी और आसपास के इलाकों में हुए समन्वित हमलों में 7 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब सुरक्षा बलों ने देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित रेनोवेशन अधिकतम सुरक्षा जेल पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया। एक रात पहले ही कैदियों ने तीन हाई-सिक्योरिटी जेलों पर कब्जा कर 46 जेल प्रहरियों को बंधक बना लिया था। बढ़ते तनाव को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में सोमवार को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सैन्य गश्त भी तेज कर दी गई है। जेलों से बाहर भी हिंसा का असर अधिकारियों के अनुसार, जेलों में बंद गैंग लीडर्स ने बाहर मौजूद अपने साथियों को जवाबी हमलों के आदेश दिए। इसी के चलते राजधानी में पुलिस को निशाना बनाया गया। गृह मंत्री मार्को एंटोनियो विलेदा ने बताया कि इन हमलों में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि एक गैंग सदस्य भी मारा गया।

सुरक्षा बलों की कार्रवाई : एंटी-रायट पुलिस ने एस्कुइंटला स्थित जेल में धावा बोलकर 9 बंधक प्रहरियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया। इस दौरान भारी गोलीबारी हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी प्रहरी सुरक्षित पाए गए। हालांकि, अब भी दो अन्य जेलों में 30 से अधिक गार्ड बंधक बने हुए हैं। पुलिस और सेना की संयुक्त टीमें लगातार हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा राज्य अपराधियों के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने इसे सरकार द्वारा संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान का परिणाम बताया।

ईरान के राष्ट्रपति बोले- खामेनेई पर हमले को जंग मानेंगे

ट्रम्प ने कहा था- प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रहीं तो हम दखल दे सकते हैं

तेहरान, एजेंसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमला हुआ, तो इसे ईरान के खिलाफ जंग माना जाएगा। पजशकियान ने एक्स पर पोस्ट कहा कि किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। पजशकियान की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों के बाद आई है। ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी जारी रहीं, तो अमेरिका दखल दे सकता है। ईरान में 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 5,000 लोगों की मौत हो गई है। इनमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी शामिल है। एक ईरानी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। दावा- ट्रम्प के दबाव में 800 लोगों की फांसी रुकी

ट्रम्प ने 15 जनवरी को बताया था कि हत्याएं अब कम हो रही हैं। व्हाइट हाउस ने भी दावा किया कि ट्रम्प के दबाव के बाद ईरान ने 800 लोगों की फांसी की योजना रोक दी है। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव मार्था पोबी ने परिषद को बताया कि ये प्रदर्शन तेजी से फैले। इसमें काफी जान-माल का नुकसान हुआ है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, अब तक 3,428 प्रदर्शनकारियों को मार डाला गया, जबकि 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सका है।

क्राउन प्रिंस पहलवी बोले- जल्द ईरान लौटूंगा : ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कहा है कि वह जल्द ईरान लौटेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। पेरिस से जारी किए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, आज ईरान में लड़ाई कब्जे और आजादी के बीच है। ईरानी जनता ने मुझे नेतृत्व के लिए बुलाया है। मैं ईरान लौटूंगा। पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वह एक 'मुक्त ईरान' का सपना देखते हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक की नीतियों से पूरी तरह अलग होगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य शांति, समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ओर लौटना है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान में लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो देश अपना परमाणु सैन्य कार्यक्रम खत्म करेगा, आतंकी संगठनों को समर्थन बंद करेगा और अमेरिका के साथ संबंध सामान्य करेगा। पहलवी ने यह भी कहा कि एक मुक्त ईरान इजराइल को मान्यता देगा और मध्य-पूर्व में स्थिरता लाने वाली ताकत बनेगा।

अमेरिका ने ईरानी नेतृत्व पर नए प्रतिबंध लगाए : ट्रम्प प्रशासन ने 18 ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ नए प्रतिबंधों लगाए हैं। इनमें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी और कई अन्य अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई की योजना बनाई। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ट्रम्प ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं और उन्होंने वित्त मंत्रालय को प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।' ईरान पहले से ही कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।

ईरान के हिंसक प्रदर्शनों में 5000 मौत, 24000 गिरफ्तार; सरकार बोली- आतंकवादियों ने मचाया कोहराम

तेहरान, एजेंसी। ईरान में अब तक हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 5000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें लगभग 500 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। ईरानी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी और कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप 'आतंकवादियों और सशस्त्र दंगाइयों' पर लगाया गया है। अधिकारी ने बताया कि ये आंकड़े पुष्टि किए जा चुके हैं। वहीं ईरानी अधिकारियों ने हिंसा के लिए बार-बार विदेशी दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और स्वीकार किया कि 'कई

हजार' लोग मारे गए हैं। ईरानी अधिकारी के अनुसार, ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को आर्थिक बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में शुरू हुए थे। शुरुआत में लोग रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन दो हफ्तों के भीतर स्थिति तेजी से बिगड़ गई और आंदोलन ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। कई शहरों में सरकार विरोधी नारे लगाए गए और धार्मिक शासन को खत्म करने की मांग उठने लगी। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समूह ने शनिवार को बताया कि उसने कम से कम 3308 मौतों को दर्ज किया है, जबकि 4382 अन्य मामलों की जांच चल रही है। समूह ने कहा कि 24000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी अधिकारी ने इन अनुमानों का खंडन करते हुए कहा कि पुष्टि की गई मृतकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल और विदेश स्थित सशस्त्र समूहों ने अशांति में शामिल लोगों का समर्थन किया और उन्हें हथियार मुहैया कराए।

ग्रीनलैंड पर ट्रंप के 'दोस्त' फिनलैंड के राष्ट्रपति ने सुना दी खरी-खरी

हेलसिंकी , एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने के लिए डेनमार्क और अन्य यूरोपीय सहयोगियों पर 10 से 25 प्रतिशत तक टैरिफ की धमकी दी, तो यूरोप में हलचल मच गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब ट्रंप के करीबी 'दोस्त' और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने खुलकर अमेरिका को सुनाया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए उन्होंने जोर दिया कि सहयोगी देशों के बीच विवादों को राजनीतिक या आर्थिक दबाव के बजाय संवाद और साझा नियमों के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। यूरोपीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर बल देते हुए स्टब ने फिनलैंड के डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने चेतावनी दी कि संभावित अमेरिकी टैरिफ ट्रांसअटलांटिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक खतरनाक दुष्चक्र को जन्म दे सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फिनलैंड इस सिद्धांत पर चलता है कि सहयोगी देशों के बीच मामले बातचीत और साझा नियमों के माध्यम से सुलझाए जाते हैं, दबाव बनाकर नहीं। सहयोगियों के साथ मिलकर आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करना फिनलैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेनमार्क के नेतृत्व में और सहयोगियों के समन्वय से ग्रीनलैंड में चल रही गतिविधियों का भी यही उद्देश्य है। यूरोपीय देश एकजुट हैं। हम क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांतों पर जोर देते हैं। हम डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। इससे पहले, नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ के मद्देनजर उनका देश यूरोपीय संघ आयोग के साथ चर्चा कर रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमने राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ संबंधी घोषणा पर ध्यान दिया है। ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास से जुड़े प्रयास आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा में योगदान देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स अपनी प्रतिक्रिया के बारे में यूरोपीय संघ आयोग और साझेदारों के साथ निकट संपर्क में है। शनिवार को ट्रंप ने ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों को धमकी दी कि अगर वे ग्रीनलैंड को बेचने के लिए सहमत नहीं हुए तो उन पर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, और उन्होंने इस क्षेत्र में चीन और रूस के हितों का हवाला दिया। उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ बातचीत की पेशकश की, लेकिन चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 फरवरी 2026 से 10 प्रतिशत टैरिफ और 1 जून 2026 से 25 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि वर्षों तक अमेरिकी समर्थन के बाद अब डेनमार्क के लिए कुछ वापस देने का समय आ गया है।

आम चुनाव में पूर्व पीएम ओली के लिए चुनौती बनेंगे ये युवा नेता, बालेन शाह से गगन थापा तक दौड़ में

काठमांडो , एजेंसी। नेपाल में कड़ाके की ठंड के बावजूद चुनाव प्रचार ने सियासी गर्मी बढ़ा रखी है। तीन राजनीतिक दलों ने 5 मार्च को होने वाले आम चुनावों के लिए अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने हाल ही में अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आधिकारिक तौर पर अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है।

वहीं नेपाल की सबसे पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस और नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने-अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों को 50 वर्ष से कम आयु का घोषित किया है। बीते सप्ताह 49 वर्षीय गगन थापा नेपाली कांग्रेस (एनसी) के अध्यक्ष चुने गए। उनके चुनाव के तुरंत बाद पार्टी के उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्मा ने एलान किया कि थापा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।

गगन थापा के खिलाफ देउबा क्यों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता चरण प्रसाई ने कहा, 'नेपाली कांग्रेस के सक्रिय नेता गगन थापा, जो जेन जी के युवाओं की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, का अध्यक्ष पद पर चुनाव होने से वर्तमान चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है।' हालांकि, नेपाली कांग्रेस के एक अन्य गुट, जिसका नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा कर रहे हैं, ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें थापा के नेतृत्व वाले गुट को आधिकारिक तौर पर वास्तविक राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता दी गई है।

बालेन शाह आरएसपी के पीएम पद के उम्मीदवार : इंजीनियर और गायक से राजनेता बने 35 वर्षीय बालेंद्र शाह 2022 में भारी बहुमत से काठमांडो महानगरपालिका के महापौर चुने गए थे। वह बालेन शाह के नाम से भी मशहूर हैं और काठमांडो के साथ पूरे देश में युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार

के रूप में महापौर चुनाव जीतने वाले बालेन अब अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए हैं और आम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वे 20 जनवरी को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकें। सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष ओली को बालेन चुनौती देंगे, जिनकी उम्र उनसे आधी है। दोनों ने झापा-पांच निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिससे पूर्वी नेपाल के कोशी प्रांत का यह जिला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ओली के लिए कैसे चुनौती बने बालेन शाह? 2008 में हुए आम चुनाव को छोड़कर ओली पिछले तीन दशकों में छह बार झापा जिले से संसद के लिए चुने गए हैं। 2022 में हुए पिछले आम चुनाव में ओली ने नेपाली कांग्रेस के अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 28,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार ओली का मुकाबला लोकप्रिय युवा नेता बालेन से है, जिनकी उम्र उनसे आधी है। बालेन नेपाल की उभरती युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ओली रूढ़िवादी और कट्टरपंथी विचारधारा का चेहरा हैं।

पूर्व पीएम ओली के खिलाफ फूटा था जेन जी का गुस्सा जेन जी के युवाओं के पिछले साल सितंबर में हुए आंदोलन में 77 लोगों की मौत हो गई थी। जेन जी ने आरोप लगाया था कि इस आंदोलन को दबाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक ने हद से ज्यादा बल प्रयोग किया। गौरतलब है कि सैकड़ों आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के बलुवाटार स्थित प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ की थी। इसके चलते ओली को एक सेना के हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कोहरे के कारण दर्जनों ट्रेनें लेट, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जारी की सूची

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोहरे के कारण उत्तर भारत में करीब 99 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली की ओर आ रही हैं। कई ट्रेनें छह से सात घंटे तक देरी से चल रही हैं। इनमें बरौनी नई दिल्ली, दरभंगा नई दिल्ली जैसी क्लोन ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे ने देरी से चल रही ट्रेनों की सूची जारी की है। यात्री घर से निकलने से पहले सूची देखें और परेशानी से बचें। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक कोहरे की वजह से ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। उत्तर भारत में कई जगह घना कोहरा छाया होने की वजह से विजीबिलिटी बहुत कम है। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है। देरी से चलने वाली ट्रेनों में 22823 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 12301 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 12313 सियालदाह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 12259 सियालदाह-बीकानेर दूरंतो एक्सप्रेस, 12225 कैफियत एक्सप्रेस, 12309 राजेंद्रनगर टर्मिनल-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, 54044 हिसार-जींद पैसेंजर, 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस (भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक), 64111 शकूरबस्ती-खुर्जा मेमू, 22437 प्रयागराज-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस, 12393 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 12559 शिव गंगा एक्सप्रेस, 12435 जयनगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 15565 वैशाली एक्सप्रेस, 12581 मंडुआडीह-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 64581 हाथरस किला-दिल्ली मेमू, 15705 दिल्ली-कटिहार अमृत भारत एक्सप्रेस, 12877 रांची-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 02563 बरौनी-नई दिल्ली हमसफर स्पेशल, 12349 कोलकाता-भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22361 पटना-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस, 12419 गोमती एक्सप्रेस, 12429 लखनऊ-नई दिल्ली राजधानी, 12557 सत्याग्रह एक्सप्रेस, 64567 अलीगढ़-खुर्जा मेमू आदि शामिल हैं, जो कई जोनों जैसे एनसीआर जोन, नार्दन जोन, और ईस्टर्न जोन से चलती हैं और ज्यादातर सुपरफास्ट, राजधानी, हमसफर, दूरंतो या एक्सप्रेस कैटेगरी की हैं, जबकि कुछ मेमू और पैसेंजर ट्रेनें भी हैं।

बेंगलुरु में 25 वर्षों के बाद नगर निकाय चुनाव बैलट पेपर से

बेंगलुरु (एजेंसी)। बेंगलुरु में 25 वर्षों के बाद नगर निकाय चुनाव बैलट पेपर से होने है। कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के तहत आने वाले 5 नई नगर निगमों के चुनावों के लिए ईवीएम की बजाय पारंपरिक बैलट पेपर से करने का निर्णय किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी.एस. संगरेशी ने बताया कि यह फैसला कानूनी रूप से वैध है और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करता। पिछली बार बेंगलुरु में बैलट पेपर का इस्तेमाल 2000 में हुआ था, उसके बाद ईवीएम का प्रयोग होता रहा। चुनाव 25 मई के बाद और 30 जून से पहले संपन्न कराए जाएंगे, ताकि 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं पर असर न पड़े। इस चुनाव में करीब 88.91 लाख मतदाता शामिल हो सकते है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि इस साल के अंत में होने वाले जिला और तालुक पंचायत चुनाव भी बैलट पेपर से होगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाताओं का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। मतगणना में देरी की चिंता नहीं है, क्योंकि पर्याप्त लॉजिस्टिक व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। चुनाव एक ही दिन में संपन्न कर परिणाम घोषित करने की योजना है। जीबीए के तहत 5 नगर निगमों सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बेंगलुरु में कुल 369 वार्ड हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची 19 जनवरी को जारी की गई, आपत्तियां 20 जनवरी से 3 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं और अंतिम सूची 16 मार्च को प्रकाशित होगी। यह निर्णय पिछले साल कर्नाटक कैबिनेट की सिफारिश के अनुरूप है और कांग्रेस सरकार ने लागू किया है। पार्टी ने पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। बैलट पेपर वापसी से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं का भरोसा मजबूत होगा।

कोकराझार में युवक की हत्या के बाद तनाव...भड़की हिंसा में अब तक दो लोगों की मौत

कोकराझार (एजेंसी)। पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में युवक की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। घटना के बाद भड़की हिंसा में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जिले के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह ठप है। मृतकों की पहचान सुनील मुर्मू और सिखना ज्वह्नलाओ बिस्मित के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, गौर नगर इलाके में एक सड़क हादसे के बाद दो समूहों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि उग्र भीड़ ने सिखना ज्वह्नलाओ बिस्मित की पीट-पीटकर हत्या कर दी। सिखना, लोकल ठेकेदार बरोंडा बसुमतारी के दामाद थे, जो क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य से जुड़े हैं। घटना के विरोध में भड़के प्रदर्शन के दौरान सुनील मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने करीगांव इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दो अस्थायी बिरसा कमांडो फोर्स कैंपों को आग के हवाले करने का आरोप है। इसके अलावा सिदु कान्हू भवन में तोड़फोड़ की गई और कई दुकानों को भी आग लगा दी गई। मौके पर एक स्कॉर्पियो को जला दिया गया। स्थिति को देखकर भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी संवेदनशील इलाकों में तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने अब तक हत्या और हिंसा के मामलों में 29 लोगों को हिरासत लेकर जांच जारी है।

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का अलर्ट, यूपी में कोहरा और औली में पारा माइनस 8 डिग्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के उत्तरी इलाकों में मंगलवार को भी मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के आने का अलर्ट जारी किया गया है। यहां 5 दिन बाद आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल कई जिले कोहरे की चपेट में हैं, जिसके कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में मंगलवार को भी कोहरा छाया है। आगरा में ताज महल धुंध में छिप गया है। अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, बाराबंकी, हाथरस सहित 5 शहरों में बारिश हुई, जबकि अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले ओले भी गिरे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमौली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में नदी-नाले और झरने जम चुके हैं। औली में पारा माइनस 8 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके कारण पानी जमने लगा है। मौसम यह पूरा बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले ही होने लगा है। दरअसल, यह पश्चिम से आने वाली हवा और बादलों का एक सिस्टम है। जैसे ही यह सक्रिय होगा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी।

मनरेगा का नाम बदलकर किया गांधी जी का अपमान: राहुल गांधी

रायबरेली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने और नयी नीति बनाने को लेकर केन्द्र सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मनरेगा को लेकर जो सोच थी, उसमें पंचायतों को जिम्मेदारी देने की बात थी और उन्हें आर्थिक रुप से सक्षम बनाना था। उस दौरान दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी बने और उससे कम कहीं भी किसी को मजदूरी न मिलें। कांग्रेस सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी पावर को 'पावर कांसेप्टेड' करना चाहते हैं। वह पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथों में देना चाहते हैं। वह गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर उन्होंने गांधी जी का अपमान किया है। उन्होंने गरीब जनता की सुरक्षा को ही हटा दिया है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ''मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान'' की मंगलवार को यहां शुरुआत की। उन्होंने ऊंचाहार विधानसभा के उमरन गांव में सीधे मनरेगा मजदूरों और गांव के लोगों से संवाद किया और केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला। मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को न तो समय पर काम मिल रहा है और न ही मजदूरी का भुगतान हो पा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ग्रामीण गरीबों की रोज़ी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती, ज़रूरत इस बात की है कि मजदूरों को काम और समय पर मजदूरी मिले। केंद्र सरकार मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी तीसरी बार की सरकार की जो सोच थी, उसकी जड़ को काटा गया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। जो मजदूरी करते हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन अडानी और अंबानी के पास में चला जाए। हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी देश की जनता के रुपये अडानी और अंबानी को देने में लगे हैं।

एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने राजीव गांधी स्टेडियम में युवा खेल अकादमी के रायबरेली प्रीमियर लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। इसके अलावा सांसद राहुल गांधी मंगलवार आनंद नगर स्थित नगर पालिका के अध्यक्ष के घर पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष के बेटी की हुई शादी के बाद परिजनों को आशीर्वाद दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए।

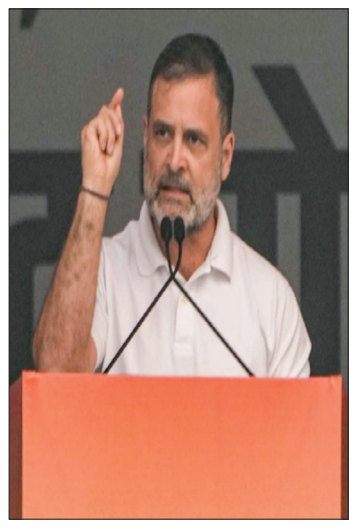

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया... उस दिन

-देश में जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए

बांदा (एजेंसी)। उत्तप्रदेश के बांदा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा बयान दिया है कि सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया, उस दिन न शर्मा न वर्मा बचने वाले हैं, न क्षत्रिय, न रैदास वाले बचने वाले है। इतना ही नहीं धीरेंद्र कृष्ण ने कहा कि न तुलसी दास वाले बचने वाले हैं, न अगड़ा बचेगा ना पिछड़ा बचेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश है। जहां एक-एक विधवा से 40-40 लोगों ने बलात्कार किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि जातिवाद नहीं इस संकट से बचाने के लिए देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस समय वहीं व्यक्ति सफल है, वहीं ताकतवर है, उसी की सत्ता है, वहीं बच सकता है जो एकजुट है। उन्होंने बताया कि मुसलमानों में 72 फिरके हैं, पठान, खान, सिया, सुन्नी मगर उनके मजहब पर बात आती है, लेकिन जब उनके मजहब पर बात आती हैं, तब सिर्फ मुसलमान हैं। हमारे भारत में 9 राज्यों में हिंदुओं की घटती हुई आबादी इसका बात कि सूचक है कि हम हिंदू हैं, मगर हम एक नहीं हो सके। हिंदू विचारधारा वाले लोगों के अलावा किसी भी हिंदू से अगर पूछो, तब वह या अपने को वर्मा बताता है या शर्मा बताता है या फिर पंडित बताता है या अन्य। मगर मेरी सबसे प्रार्थना है कि हमारा परिचय जाति से नहीं हिंदू से होना चाहिए। हिंदुओं को बचाने का एकमात्र यही रास्ता है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं, तब हिंदुओं के क्यों नहीं? इसलिए हिंदुओं के बेटे 4 यही लगाएंगे बेड़ा पार। 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चा स्वयं सेवक संघ के लिए व 1 बच्चा हिंदू राष्ट्र के लिए।

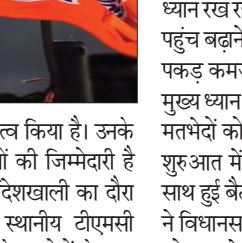

रियासत को तोड़ने वाले बहुत से लोग हैं, वे कभी कामयाब नहीं होंगे

-नए जिले बनाने की मांग पर महबूबा को फारूक अब्दुल्ला ने दिया जवाब

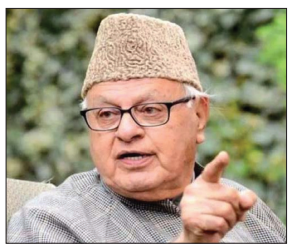

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की जम्मू संभाग में नए जिले बनाने की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रियासत को तोड़ने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई नया जिला नहीं बनाया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन में कहा कि हम लोग अपने ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक सचिवों को सुन रहे हैं। उनकी तकलीफों को सुन रहे हैं और उन्हें किस प्रकार मजबूत किया जाए, इस पर विचार कर रहे हैं।

महबूबा मुफ्ती के नए जिलों की मांग पर उन्होंने कहा कि कोई जिला नहीं बनना चाहिए। पहले से ही बहुत जिले हैं। इन्हें कोई संभाल सके वही बड़ी बात है। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि वह भी सीएम रहीं हैं और उनके पिता भी सीएम थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन देखना चाहिए कि तीन उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डिक्सन प्लान बहुत पुराना था कि डिवाइड करो। चिनाब नदी के उस पार ग्रेटर कश्मीर है, और इसे अलग करो। हिमाचल के परमार साहब थे, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा के लोगों से कहा कि आपकी जुबान हिमाचली है, वरना तो बहुत बड़े-बड़े ख्याल थे। रियासत को तोड़ने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं होंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू को नासमझ बताते हुए कहा कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम तो लद्दाख को भी अलग नहीं करना चाहते थे। उससे लद्दाखियों को क्या फायदा मिला? आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो। हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। उम्मीद है कि एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा।

बंगाल में फतह के लिए बीजेपी ने अपने अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को जमीन पर उतारा

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को रिपोर्ट करने का आदेश

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा अपनी व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है और इसके लिए बीजेपी ने अन्य राज्यों के कई अनुभवी नेताओं को चुनाव की तैयारियों में लगा दिया है। पिछले एक महीने में भाजपा ने अन्य राज्यों के कई अनुभवी वरिष्ठ नेताओं (प्रवासी सदस्य) को बंगाल इकाई में मंडल से लेकर जिला स्तर तक आंतरिक मतभेदों को सुलझाने और चुनाव की तैयारियों का प्रबंधन का काम दिया गया है। इन प्रवासी सदस्यों में उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपी एस राठौर, उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत, राजस्थान भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेश राणा, हरियाणा भाजपा के महासचिव संजय भाटिया और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सी टी रवि शामिल हैं। चूंकि ये नेता मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं, इसलिए उनके साथ स्थानीय नेता भी होते हैं जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और लोगों से बातचीत के दौरान मदद करते हैं। बंगाल में तैनाती के बाद से, इन नेताओं ने मंडल, विधानसभा और जिला इकाइयों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें की हैं।

राठौर, जिन्हें 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रबंधन का अनुभव है, को बंगाल की 35 विधानसभा सीटों की जबावदेही दी गई हैं। उनके अधीन पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोंटाई और तामलुक तथा पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के घाटाल और मेदिनीपुर शहर आते हैं। वहीं राणा उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर, बारासात और बोंगाँव का काम देख रहे हैं। राणा पश्चिमी यूपी के शामली जिले से हैं और उन्होंने हरियाणा, दिल्ली, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनावी प्रयासों का नेतृत्व किया है। उनके पास 28 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी है और हाल ही में उन्होंने संदेशखाली का दौरा किया, जहां 2024 में स्थानीय टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। वहीं भाटिया को आरामबाग उपमंडल और श्रीरामपुर सहित हुगली जिला और हावड़ा शहर सौंपा गया है, जबकि चौधरी को कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और उत्तरी बंगाल के अन्य जिलों में पार्टी की तैयारियों की निगरानी का जिम्मा मिला है। ये सभी नेता राज्य के प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को रिपोर्ट करते हैं।

अपने-अपने राज्यों के अनुभव के आधार पर हम राजनीतिक और संगठनात्मक प्रबंधन की देखरेख कर रहे हैं। हम संगठनात्मक अभियानों और कार्यक्रमों का भी ध्यान रख रहे हैं और उन मतदान केंद्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमारी पकड़ कमजोर दिख रही है। हालांकि, हमारा मुख्य ध्यान लोकल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मतभेदों को सुलझाने पर ज्यादा है। महीने की शुरुआत में पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं के साथ हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनावों से पहले सभी मतभेदों को भुलाने का निर्देश दिया था। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने इस बैठक को राज्य स्तर पर पार्टी के पुराने और नए नेतृत्व के बीच की खाई को पाटने का प्रयास बताया। हालांकि, टीएमसी ने पिछली बार भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी के रूप में पेश करने में सफलता हासिल की थी और इस बार भी वही कहानी दोहरा रही है, इसके बाद भाजपा इसका क्या जवाब देती है, यह देखना बाकी है।

जब ज्योतिषपीठ के अधिकृत नहीं तो कैसे कर रहे 'शंकराचार्य' शब्द का प्रयोग

-धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

प्रयागराज (एजेंसी)। प्रयागराज संगम में मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोकने और शिष्यों के साथ मारपीट करने का विवाद बढ़ा ही जा रहा है। संगम में स्नान से इनकार करने और धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए पूछा कि संबंधित व्यक्ति ज्योतिषपीठ के अधिकृत शंकराचार्य नहीं हैं, ऐसे में वे अपने नाम के साथ 'शंकराचार्य' शब्द का प्रयोग किस आधार पर कर रहे हैं? नोटिस में मेला प्रशासन ने 24 घंटे में लिखित जवाब मांगा है। इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वे किस वैधानिक या धार्मिक आधार पर स्वयं को शंकराचार्य कहते हैं। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठ के

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के लंबित मुकदमे का जिक्र किया गया है। नोटिस प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मेला क्षेत्र में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों और शिविरों को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है। सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक आयोजनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। किसी भी पद, उपाधि या पहचान का गलत इस्तेमाल प्रशासन के लिए गंभीर विषय माना जा रहा है।

नोटिस के बाद संत के समर्थकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि शंकराचार्य एक परंपरागत धार्मिक पद है और इस पर प्रशासनिक हस्तक्षेप उचित नहीं। समर्थकों का आरोप है कि मेला प्रशासन धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। वहीं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह धार्मिक व्यक्ति ही क्यों न हो। सुप्रीम कोर्ट के प्रार्थना पत्र के उपरोक्त खंड को पूर्णतया स्वीकार करते हुए 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया गया था। नोटिस में कहा गया है कि इस अपील संख्या की ताजा स्थिति के रूप में कोई अन्य आदेश पारित नहीं हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपील का निस्तारण नहीं कर दिया जाता या कोई अग्रिम आदेश प?ट्टाभिषेक के मामले में पारित नहीं होता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के तौर पर सुशोभित नहीं हो सकता है।

मुंबई मेयर के लिए जादुई आंकड़े 114 से महज 6 कदम दूर हैं हम

-बीएमसी के सिंहासन पर कब्जा करने शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने फोड़ा बम

मुंबई (एजेंसी)। देश की सबसे अमीर मुंबई महानगरपालिका बीएमसी के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए खेल अब तीखा और पेंचीदा हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बम फोड़ा है, जिसने महायुति के खेमे में खलबली मचा दी है। राउत ने दावा किया कि वे बहुमत के जादुई आंकड़े 114 से महज 6 कदम दूर हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये 6 कदम कहां से पूरे होंगे?

संजय राउत जब कहते हैं कि उनके पास 108 का आंकड़ा है जिसमें उद्धव गुट (65), कांग्रेस (24), शरद पवार की एनसीपी और अन्य छोटे दलों को मिलाकर भी यह आंकड़ा 108 तक नहीं पहुंचता। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी पर्दे के पीछे से

उद्धव ठाकरे को समर्थन देने को तैयार है? सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए उद्धव अब ओवैसी के साथ जाने का जोखिम उठाएंगे?

अगर 108 के आंकड़े में मुस्लिम बहुल सीटों वाले पार्षद शामिल होते हैं, तो इसका मतलब साफ है, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्षी गठबंधन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि शिंदे अपने ही पार्षदों से डरे हुए हैं। राउत के मुताबिक शिंदे सेना के पार्षदों को बांद्रा और कल्याण-डोंबिवली के तीन अलग-अलग होटलों में नजरबंद किया गया है। राउत का दावा है कि जो शिंदे कल तक ईडी के डर से उद्धव का साथ छोड़ गए थे, आज उन्हें डर है कि उनके पार्षद पाला बदल लेंगे। राउत ने कहा कि हमारे (यूबीटी) पार्षद खुलेआम घूम रहे हैं, घरों पर मजे कर रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं।

रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी चुनाव के बाद भले ही महायुति सबसे मजबूत दिख रही हो, लेकिन अंदरूनी कलह चरम पर है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अपना मेयर चाहती है। सूत्र बताते हैं कि वे ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर भी राजी नहीं हैं और साफ कह चुकी है 30 जनवरी को बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा। एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों के दम पर ढाई साल का मेयर पद या सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष पद मांग रहे हैं।

इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारत में बने हथियार होंगे आकर्षण का केंद्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में सेना की नवगठित 'भैरव' लाइट कमांडो बटालियन, 'शक्तिबाण' तोपखाना रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स माउंटेन इन्फैंट्री रेजिमेंट प्रमुख आकर्षण होंगे। यही नहीं, वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के दसॉ राफेल और स्वदेशी रूप से निर्मित रूसी मूल के सुखोई एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमान भी उड़ान भरेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी और कहा कि इनमें कई उपकरण और रेजिमेंट को पहली बार युद्ध की तैयारी जैसी संचालन के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस साल के गणतंत्र दिवस की थीम 'वंदे मातरम के 150 वर्ष' है। परेड में 30 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें से छह राष्ट्रीय गीत को समर्पित होंगी। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य मामलों में बढ़ी आम जानता की रुचि को देखते हुए रक्षा सचिव ने कहा कि इन उपकरणों और बटालियनों के प्रदर्शन का उद्देश्य देश को सशस्त्र बलों की परिचालन व्यवस्था को दिखाना है।

उन्होंने कहा कि विचार है कि युद्ध में उपकरणों और जनशक्ति को एक साथ कैसे लाया जाता है, इसकी एक कहानी सबके सामने लाना है। उन्होंने कहा कि इससे गणतंत्र दिवस समारोह और इसकी यह परेड आम लोगों के लिए अधिक आकर्षक और जानकारीपरक हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले कुछ कर्मी इस तरह प्रदर्शन करेंगे मानो वे पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हों। आत्मनिर्भरता के विषय को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी और मेड-इन-इंडिया सिस्टम से जुड़ी उपलब्धियां भी परेड में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, इंडो-रूसी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, जिनका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया था।

रक्षा सचिव ने कहा कि परेड में दिखाई जाने वाली युद्धक सामग्री, उपकरण, प्रणाली का बड़ा हिस्सा या तो भारत में बना है या यहां डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय रूप से एयरबस सी295 परिवहन विमान, जो अब टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा भारत में बनाए जाते हैं, अमेरिकी मूल के एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर और सी-130जे सुपर हर्क्यूलिस परिवहन विमान भी देश को इस परेड में देखने को मिलेंगे। इस बार स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परेड में भाग नहीं लेगा। सूत्रों ने संकेत दिया कि वीआईपी की उपस्थिति को देखते हुए एकल-इंजन विमान को ऐसे आयोजनों के लिए आदर्श नहीं माना जाता। परेड का एक और आकर्षण होगा देश का ड्रोन तंत्र। इन ड्रोन को उड़ाया नहीं जाएगा, ये केवल प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे। इसका कारण भी सूत्रों ने परेड स्थल पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति बताया है।